RNI No. MPHIN/2015/64451 डाक पंजीयन क्र. MP/IDC/1525/2019-2021 IPT डाक द्वारा प्रेषण प्रति शुक्रवार indianplasttimes@gmail.com

www.Indianplasttimes.in

इंडियन प्लास्ट टाइम्स

■ INDORE ■ 15 SEPTEMBER TO 21 SEPTEMBER 2021 ■ प्रति बुधवार ■ वर्ष 07 ■ अंक 3 ■ पृष्ठ 8 ■ कीमत 5 रु.

Inside News

जीएसटी का असरः ...तो पेट्रोल 75 रुपये और डीजल 68 रुपये प्रति लीटर मिलेगा? Page 2

बक्सवाहा के शैल चित्र बंदर हीरा परियोजना से काफी दूर... Page 5

किसानों के लिए घाटे का सौदा साबित हो रही मिर्च की खेती, तुड़वाने की लागत निकालना भी मुश्किल Page 7

editoria!

वैक्सीन और अर्थव्यवस्था

डेढ़ साल से अधिक समय से जारी महामारी आर्थिक विकास की राह में बड़ी बाधा साबित हुई है. कोरोना वायरस के संक्रमण से स्थायी बचाव का एक ही उपाय है कि व्यापक स्तर पर लोग टीकों की खुराक लें. इसीलिए वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण का यह कहना पूरी तरह से सही है कि अर्थव्यवस्था में बढ़ोतरी की दवाई टीकाकरण है. अब तक देश के 73 करोड़ लोगों को टीके की पहली या दोनों खुराकें दी जा चुकी हैं. इससे एक तो उनका बचाव सुनिश्चित हो गया है क्योंकि अब तक के अनुभवों के आधार पर कहा जा सकता है कि जिन लोगों ने वैक्सीन ली है, वे या तो संक्रमण की चपेट में नहीं आते या अगर वे संक्रमित होते भी हैं, तो उन्हें गंभीर बीमारी नहीं होती. ऐसे लोग बिना किसी डर या आशंका के अपने कारोबारी या पेशेवर जिम्मेदारियों को निभा रहे हैं. जब आर्थिक गतिविधियों में तेजी आयेगी, तभी आर्थिक वृद्धि दर में भी बढ़ोतरी होगी. महामारी की दूसरी लहर, जो पिछले साल की तुलना में बहुत अधिक आक्रामक संक्रमण लेकर आयी थी और देश के बड़े हिस्से में अफरातफरी मच गयी थी, के दौरान वृद्धि दर के संतोषजनक रहने के पीछे टीकाकरण अभियान का बड़ा योगदान रहा है. चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही (अप्रैल-जून) के नतीजों के आधार पर शेष तिमाहियों की दरों के उत्साहजनक रहने की उम्मीदें मजबूत हो गयी हैं. बीते दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेखांकित किया है कि कोरोना महामारी से नुकसान की तुलना में आर्थिक भरपाई अधिक तेजी से हो रही है. पहली लहर के समय संक्रमण पर अंकुश लगाने के लिए लॉकडाउन लगाना पड़ा था. तीन माह से अधिक के लॉकडाउन के बाद भी कई महीनों तक देश के अलग-अलग हिस्सों में कई तरह की पाबंदियां लगानी पड़ी थीं. इस वजह से पिछले वित्त वर्ष की पहली दो तिमाहियों में वृद्धि दर ऋणात्मक हो गयी थी यानी, तकनीकी रूप से वह आर्थिक मंदी का दौर था. उस अनुभव के कारण दूसरी लहर के असर को लेकर देश आशंकित था, किंतु टीकाकरण अभियान तथा सरकार के राहत उपायों ने अर्थव्यवस्था को बड़ा आधार दिया. संक्रमण के हजारों मामले अब भी आ रहे हैं और कुछ राज्यों में महामारी का प्रकोप बहुत अधिक है. इससे तीसरी लहर की आशंका भी है. यह ठीक है कि अब तक के अनुभवों से लाभ उठाते हुए किसी भी स्थिति का सामना किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए सबसे अधिक जरूरी यह है कि आबादी के बड़े हिस्से में संक्रमण को रोकने की प्रतिरोधी क्षमता आ जाए. करोड़ों लोगों ने अब भी टीके की खुराक नहीं ली है. कुछ समय से टीकों की आपूर्ति तेजी से बढ़ी है और हर रोज वैक्सीन लेनेवालों की संख्या में बढ़त हो रही है. अब अभियान को उन लोगों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, जिनमें हिचक है. आर्थिक वृद्धि बरकरार रहे, इसके लिए संक्रमण से पूर्ण बचाव जरूरी है.

ऑटो-टेलीकॉम सेक्टर के लिए सरकार ने खोला खजाना

एजीआर बकाये पर किए गए ये बड़े ऐलान

नई दिल्ली। आईपीटी नेटवर्क

कोरोना की मार झेल रही ऑटो इंडस्ट्री को बड़ी राहत मिली है। दरअसल, केंद्र सरकार की कैबिनेट ने ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए प्रोडक्शन-लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम को मंजूरी दी है। इस स्कीम में ऑटो कंपोनेंट और ड्रोन सेक्टर भी शामिल हैं। ये स्कीम पांच साल के लिए लागू रहेगी। इससे ऑटोमोबाइल सेक्टर में निवेश बढ़ने की उम्मीद है। वहीं, आयात में भी कमी आने की उम्मीद है।

ऑटो सेक्टर को कितने रुपये मिलेंगे

कैबिनेट की बैठक की जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि केंद्र सरकार ने ऑटो सेक्टर के लिए 25,938 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं। इसके तहत इलेक्ट्रि?क वाहनों के उत्पादन, हाइड्रोजन फ्यूल व्हीकल उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा। वहीं, 7.60 लाख लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है। इस स्कीम के आने से विदेश से आयात में गिरावट होगी। ऑटो कंपोनेंट मेक इन इंडिया के तहत देश में बनाए जा सकेंगे। अनुराग ठाकुर ने बताया कि चयनित चैंपियन ऑटो कंपनियों को कम से कम 2 हजार करोड़ रुपये का निवेश करना होगा। वहीं, नए निवेशकों को 500 करोड़ रुपये का निवेश करना जरूरी है।

टेलीकॉम को क्या मिला

टेलीकॉम सेक्टर के लिए भी राहत पैकेज देने की बात कही गई है। टेलीकॉम मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने बताया कि टेलीकॉम सेक्टर में 9 बड़े स्ट्रक्चरल रिफॉर्म हुए हैं। समायोजित सकल राजस्व (एजीआर) बकाये के परिभाषा में बदलाव किया जाएगा। एजीआर से जूझ रहे टेलीकॉम सेक्टर के लिए ये बड़ी खबर है। इसकी मांग टेलीकॉम कंपनियां भी कर रही थीं। टेलीकॉम कंपनियों को मंथली इंटरेस्ट रेट को अब एनुअल कर दिया गया है। इसके अलावा पेनल्टी पर भी राहत दी गई है। स्पेक्ट्रम की अवधि भी अब 20 साल से बढ़ा कर 30 साल कर दिया गया है। टेलीकॉम ऑपरेटर्स बकाये को लेकर मोरेटोरियम ले सकेंगे। ये 4 साल तक के लिए दिया गया है। जो टेलीकॉम ऑपरेटर ये विकल्प चुनते हैं उन्हें सरकार को ब्याज भी देना होगा। बता दें कि एजीआर बकाये की वजह से वोडाफोन आइडिया और एयरटेल पर वित्तीय बोझ बढ़ा है। राहत की इस खबर के बीच एयरटेल और वोडाफोन-आइडिया के शेयर में बड़ी तेजी देखने को मिली है।

अमेरिकी डिमांड से महंगा हुआ कच्चा तेल, यहां 10वें दिन भी बदलाव नहीं

नई दिल्ली। दुनिया में कच्चे तेल के सबसे बड़े ग्राहक अमेरिका में एक बार फिर से कच्चे तेल की खपत बढ़ी है। अमेरिकन पेट्रोलियम इंस्टीच्यूट के आंकड़ों के अनुसार 10 सितंबर को समाप्त सप्ताह में वहां 5.437 मिलियन बैरल कच्चे तेल का ड्रॉ हुआ है। इससे पहले के सप्ताह में 2.882 मिलियन बैरल क्रूड का ड्रॉ हुआ था। इस वजह से कल कच्चे तेल का बाजार और चढ़ गया। लेकिन, भारत में देखें तो यहां सरकारी तेल कंपनियों ने लगातार 10वें दिन भी पेट्रोल और डीजल के दाम में कोई फेरबदल नहीं की। इससे पहले शिक्षक दिवस के दिन पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 15-15 पैसे की कमी हुई थी। दिल्ली के बाजार में बुधवार को इंडियन ऑयल के पंप पर पेट्रोल प्रति लीटर 101.19 रुपये पर टिका रहा। डीजल का दाम भी 88.62 रुपये प्रति लीटर पर स्थिर है।

इस साल मई से जुलाई के बीच 11.52 रुपये महंगा हो चुका है पेट्रोल

इस साल की पहली तिमाही के दौरान कई राज्यों में विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया चलने की वजह से बीते मार्च और अप्रैल में पेट्रोल की कीमतों में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई थी। इसलिए, उस दौरान कच्चा तेल महंगा होने के बाद भी पेट्रोल-डीजल के दाम में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई। लेकिन, बीते चार मई से इसकी कीमतें खूब बढ़ी। कभी लगातार तो कभी ठहर कर, 42 दिनों में ही पेट्रोल 11.52 रुपये प्रति लीटर महंगा हो गया है। हालांकि, हरदीप सिंह पुरी के पेट्रोलियम मंत्री बनने के बाद बीते 18 जुलाई से इसके दाम स्थिर थे। रक्षा बंधन के दिन, इसके दाम में महज 20 पैसे की कमी की गई थी। उसके दो दिन बाद भी 15 पैसे की कमी हुई है। उसके बाद एक सितंबर और पांच सितंबर को इसके दाम फिर 15-15 पैसे घटे।

पेट्रोल के मुकाबले थोड़ा सस्ता हुआ है डीजल

अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चा तेल भले ही सस्ता बिक रहा हो, लेकिन यहां सरकारी तेल कंपनियां उस हिसाब से कीमतों में कमी नहीं कर रही हैं। वैसे भी डीजल (अ्गोत) महंगा ईंधन होने के बावजूद भारत में यह पेट्रोल के मुकाबले सस्ता बिकता है। इस साल के शुरूआती महीनों के दौरान कुछ राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए थे। उस दौरान 41 दिनों तक डीजल के दाम में कोई फेरदबल नहीं हुआ था। उस समय डीजल के दाम में अंतिम कमी बीते 15 अप्रैल को हुई थी। उस समय 14 पैसे की कमी हुई थी। लेकिन बीते 4 मई से इसमें जो ठहर-ठहर कर बढ़ोतरी हुई, उससे डीजल 9.08 रुपये प्रति लीटर महंगा हो गया है। उसके बाद बीते 16 जुलाई से इसके दाम में कोई फेरबदल नहीं हुआ था। बीते 18 अगस्त से 20 अगस्त तक इसकी कीमतों 20 पैसे प्रति लीटर की रोजाना कमी हुई है। इसके बाद रक्षा बंधन के दिन भी दाम में इतनी ही कमी हुई थी। उसके दो दिन बाद भी यह 15 पैसे सस्ता हुआ था। बीते एक सितंबर के 15 पैसे और पांच सितंबर के 15 पैसे की कमी को जोड़ लिया जाए तो पिछले एक पखवाड़े में अब तक डीजल 1.25 रुपये प्रति लीटर सस्ता हो चुका है।

News यू केन USE

KYC अपडेशन के नाम पर हो रहा फ्रॉड, RBI ने जारी किया अलर्ट

नई दिल्ली। एजेंसी

रिजर्व बैंक ने केवाईसी अपडेशन के नाम पर धोखाधड़ी को लेकर अलर्ट जारी किया है। रिजर्व बैंक ने ट्वीट में लिखा, 'अपना लॉगिन विवरण, व्यक्तिगत जानकारी, केवाईसी दस्तावेजों की प्रतियां, कार्ड की जानकारी, पिन, पासवर्ड, ओटीपी आदि अज्ञात लोगों के साथ या असत्यापित वेबसाइटों या ऐप्स द्वारा शेयर न करें।' आरबीआई ने एक अन्य ट्वीट में कहा, 'ख्ष्ण अपडेशन, कार्ड की जानकारी, इ्ब्र या ध्ऊइ के लिए किए गए मेसेज, कॉल या लिंक से सावधान रहें! हाल ही में रिजर्व बैंक ने एक सर्कुलर जारी कर बताया है कि गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (एनबीएफसी) और भुगतान प्रणाली परिचालक आधार ई-केवाईसी सत्यापन लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकते हैं। रिजर्व बैंक की ओर से जारी सर्कुलर में कहा गया है कि एनबीएफसी, भुगतान प्रणाली परिचालरक और भुगतान प्रणाली भागीदार आधार सत्यापन लाइसेंस-केवाईसी प्रयोगकर्ता एजेंसी (केयूए) लाइसेंस या उप-केयूए लाइसेंस के लिए विभाग को आवेदन कर सकते हैं जिसे आगे यूआईडीएआई (भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण) के पास भेजा जाएगा। मई, 2019 में वित्त मंत्रालय ने बैंकिंग कंपनियों को छोड़कर अन्य इकाइयों द्वारा आधार सत्यापन सेवाओं के इस्तेमाल के लिए आवेदन को विस्तृत प्रक्रिया जारी की थी।

वाणिज्य मंत्रालय : अगस्त में निर्यात 46 फीसदी बढ़कर 33 अरब डॉलर हुआ, 14 अरब डॉलर का आया व्यापार घाटा

नई दिल्ली। आईपीटी नेटवर्क

अर्थव्यवस्था में सुधार के साथ निर्यात के मोर्चे पर लगातार तेजी आ रही है। अगस्त में देश का निर्यात करीब 46 फीसदी बढ़ा, जबकि आयात में 52 फीसदी इजाफा हुआ। वाणिज्य मंत्रालय ने मंगलवार को बताया कि आयात में तेजी से व्यापार घाटा बढ़कर 14 अरब डॉलर पहुंच गया है। अगस्त में आयात भी 52 फीसदी बढ़कर 47 अरब डॉलर पहुंचा मंत्रालय के अनुसार, अगस्त में कुल 33.28 अरब डॉलर का निर्यात हुआ, जो पिछले साल की समान अवधि में 22.83 अरब डॉलर था। इसी तरह, आयात भी डेढ़ गुना बढ़कर 47.09 अरब डॉलर पहुंच गया। अगस्त, 2020 में जहां कुल व्यापार घाटा 8.2 अरब डॉलर था, वहीं इस साल यह 13.81 अरब डॉलर हो गया है। मंत्रालय ने बताया कि 2021 में अप्रैल-अगस्त तक कुल निर्यात 164.10 अरब डॉलर, जो पिछले साल की समान अवधि के 98.06 अरब डॉलर से 67.33 फीसदी ज्यादा है। आयात भी पिछले साल के 121.42 अरब डॉलर से बढ़कर 219.63 अरब डॉलर हो गया है।

शुरुआती कारोबार में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया दो पैसे चढ़ा

मुंबई। एजेंसी

भारतीय रुपया बुधवार को शुरुआती कारोबार में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले दो पैसे की तेजी के साथ 73.66 पर खुला। अमेरिका में मुद्रास्फीति के आंकड़े जारी होने से पहले डॉलर में तेजी देखी गई, जिसके चलते घरेलू मुद्रा एक सीमित दायरे में कारोबार कर रही थी। विदेशी मुद्रा कारोबारियों ने कहा कि इसके अलावा कच्चे तेल की कीमतों में तेजी ने भी रुपये की बढ़त को सीमित किया। अंतरबैंक विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में रुपया डॉलर के मुकाबले 73.68 पर खुला और फिर अपने पिछले बंद भाव के मुकाबले दो पैसे बढ़कर 73.66 पर पहुंच गया। शुरुआती कारोबार के दौरान रुपये ने 73.71 के निचले स्तर को छुआ। रुपया मंगलवार को अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 73.68 पर बंद हुआ था। इस बीच छह प्रमुख मुद्राओं के मुकाबले अमेरिकी डॉलर की स्थिति को दर्शाने वाला डॉलर सूचकांक 0.01 प्रतिशत बढ़कर 92.63 पर आ गया। वैश्विक तेल बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड वायदा 0.63 प्रतिशत बढ़कर 74.06 डॉलर प्रति बैरल के भाव पर था।

जीएसटी का असर: ...तो पेट्रोल 75 रुपये और डीजल 68 रुपये प्रति लीटर मिलेगा?

नई दिल्ली। एजेंसी

आम लोगों को पेट्रोल और डीजल की आसमान छूती कीमत से आने वाले महीनों में राहत मिल सकती है। दरअसल, सरकार पेट्रोल, डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने पर विचार कर रही है। अगर ऐसा हुआ तो देश भर में पेट्रोल के भाव 75 रुपये और डीजल के भाव 68 रुपये प्रति लीटर तक आ सकता है।

वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) पर मंत्रियों का एक पैनल एक देश और एक दर के तहत पेट्रोलियम उत्पादों पर कर लगाने पर विचार करेगा। मामले से जुड़े लोगों के मुताबिक, उपभोक्ताओं के लिए ईंधन की कीमत और सरकारी राजस्व में संभावित बड़े बदलाव के लिए यह अहम कदम हो सकता है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता वाला पैनल शुक्रवार को लखनऊ में होने वाली 45वीं जीएसटी परिषद की बैठक में प्रस्ताव पर विचार करेगा।

गौरतलब है कि केरल हाईकोर्ट की ओर से पेट्रोल व डीजल को जीएसटी के दायरे में लाए जाने के निर्देश के बाद जीएसटी काउंसिल के समक्ष यह मामला 17 सितंबर को लाया जाएगा। नाम न लेने की शर्त पर एक अधिकारी ने बताया कि राजस्व को देखते हुए जीएसएटी परिषद के उच्च अधिकारी पेट्रोलियम पदार्थों पर एक समान जीएसटी लगाने को तैयार नहीं हैं।

तीन-चौथाई सदस्यों की मंजूरी जरूरी

वहीं, विशेषज्ञों का कहना है कि पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे में थोड़ा मुश्किल है। दरअसल, जीएसटी प्रणाली में किसी भी बदलाव के लिए पैनल के तीन-चौथाई लोगों की मंजूरी जरूरी है। इस पैनल में सभी राज्यों के प्रतिनिधि शामिल हैं। इनमें से कुछ ईंधन को जीएसटी के दायरे में लाने का विरोध कर रहे हैं। उन राज्यों का मानना है कि पेट्रोल और डीजल के जीएसटी दायरे में आने के बाद राजस्व का एक अहम राज्यों के हाथों से निकल जाएगा। इस पर केंद्र सरकार को अपना रुख पहले स्पष्ट करना होगा। फिर जाकर सहमति के आसार बन सकते हैं।

सस्ते हो जाएंगे पेट्रोल-डीजल

इस साल मार्च में एसबीआई की इकोनॉमिक रिसर्च डिपार्टमेंट ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि अगर पेट्रोलियम उत्पादों को जीएसटी के दायरे में लाया जाएगा तो केंद्र और राज्यों को राजस्व में जीडीपी के महज 0.4 फीसदी के बराबर की कमी आएगी। वहीं, जीएसटी के दायरे में पेट्रोलियम उत्पादों को लाने के बाद देश भर में पेट्रोल के भाव 75 रुपये और डीजल के भाव 68 रुपये प्रति लीटर तक आ सकता है।

कोरोना की दवाइयों पर रियायत संभव

जीएसटी परिषद की 45वीं बैठक में कोविड-19 से संबंधित आवश्यक सामान पर रियायती दरों की समीक्षा हो सकती है। जीएसटी परिषद की इससे पिछली बैठक 12 जून को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये हुई थी। इसमें कोविड-19 से संबंधित सामग्री पर कर की दरों को 30 सितंबर तक के लिए घटाया गया था। इसके अलावा जीएसटी काउंसिल नवीकरणीय उपकरणों पर 12 फीसदी और लौह, तांबा के अलावा अन्य धातु अयस्कों पर 18 फीसदी जीएसटी लगाने पर विचार कर सकता है।

पेट्रोलियम उत्पादों से भरा सरकारी खजाना

सरकार का पेट्रोलियम उत्पादों पर उत्पाद शुल्क कलेक्शन चालू वित्त वर्ष के पहले चार महीनों में 48 प्रतिशत बढ़ गया है, और इस दौरान हासिल हुआ अतिरिक्त कलेक्शन पूरे वित्त वर्ष के दौरान तेल बॉन्ड देनदारी का तीन गुना है। केंद्रीय वित्त मंत्रालय के तहत लेखा महानियंत्रक के आंकड़ों के मुताबिक अप्रैल-जुलाई 2021 के दौरान उत्पाद शुल्क कलेक्शन एक लाख करोड़ रुपये से अधिक हो गया, जो पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि में 67,895 करोड़ रुपये था।

भारत, ब्रिटेन का एक नवंबर से मुक्त व्यापार समझौते पर बातचीत शुरू करने का लक्ष्य

लंदन/नयी दिल्ली। एजेंसी

भारत और ब्रिटेन ने प्रस्तावित द्विपक्षीय मुक्त व्यापार समझौते पर एक नवंबर से बातचीत शुरू करने का लक्ष्य लेकर आगे बढ़ रहे हैं। इस कदम का उद्देश्य दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश को बढ़ाना है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने मंगलवार को कहा कि दोनों देश एक व्यापक मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) को ध्यान में रखते हुए पहले एक शुरुआती समझौते पर आगे बढ़ रहे हैं। ब्रिटेन ने उम्मीद जतायी कि दोनों देशों के बीच व्यापार पर जल्द एक समझौते की मजबूत संभावना है। गोयल और ब्रिटेन की अंतरराष्ट्रीय व्यापार मंत्री एलिजाबेथ ट्रस के बीच मंगलवार को 'ऑनलाइन' बातचीत के दौरान एफटीए से जुड़े मामले आयें। भारत के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने एक बयान में कहा, ''भारत और ब्रिटेन के बीच प्रस्तावित एफटीए से दोनों देशों के लिये अभूतपूर्व व्यापार के अवसर और रोजगार सृजित होंगे। दोनों पक्षों ने परस्पर लाभ के आधार पर व्यापार को आगे बढ़ाने को लेकर प्रतिबद्धता जतायी।

इस मौके पर गोयल ने कहा कि हम दोनों देशों की कंपनियों के आर्थिक लाभ के लिये बातचीत को यथाशीघ्र अंतिम निष्कर्ष पर पहुंचाने को लेकर उत्सुक हैं। उन्होंने कहा कि प्रस्तावित समझौते को लेकर काफी काम हो चुके हैं। उद्योग, व्यापार संगठनों, निर्यात संवर्धन परिषदों, नियामकीय निकायों, मंत्रालयों तथा शोध निकायों समेत विभिन्न पक्षों के साथ गहन विचार-विमर्श किये गये हैं। इसके अलावा, विभिन्न मामलों के लिये द्विपक्षीय कार्यकारी समूह बनाये गये हैं। इसका मकसद एक-दूसरे की महत्वकांक्षा, रूचि और संवेदनशीलता को समझना है ताकि बातचीत को तेजी से आग बढ़ाने में मदद मिले। इन समूहों की बैठकें जारी हैं और सितंबर में प्रक्रिया पूरी होने की उम्मीद है।

गोयल ने कहा कि इन वार्ताओं से दोनों पक्षों को एक-दूसरे की नीतिगत व्यवस्थाओं को समझने में मदद मिलेगी। इससे नवंबर में बातचीत शुरू करने के लिए नियम एवं शर्तों को अंतिम रूप देने को लेकर दोनों पक्ष एक अक्टूबर से शुरू होने वाले बातचीत को लेकर बेहतर स्थिति में होंगे। उन्होंने कहा, ''अंतरिम व्यापार समझौता एफटीए की दिशा में पहला कदम है। इससे हम आपसी साझेदारी के जरिये जल्दी लाभ उठा पाएंगे।'' गोयल ने कहा कि भारत और ब्रिटेन एक व्यापक एफटीए को लेकर अंतरिम व्यापार समझौते की दिशा में कदम बढ़ाकर व्यापार संबंधों को सुदृढ़ कर रहे हैं। ब्रिटेन की अंतरराष्ट्रीय व्यापार मंत्री ट्रस ने ट्विटर पर लिखे बयान में आगामी ब्रिटेन-भारत व्यापार समझौते की आधारशिला रखने के लिए व्यापार कार्य समूहों के गठन की घोषणा की। उन्होंने कहा, ''पीयूष गोयल और मैंने आज व्यापार कार्यकारी समूहों का गठन किया। यह आगामी बिटेन-भारत व्यापार समझौते के लिये आधारशिला का काम करेंगे...।''

आवास मूल्य सूचकांक

भारत 55 देशों की सूची में 54वें स्थान पर

सिर्फ इंडिया और स्पेन में ही मकान सस्ते हुए

नई दिल्ली। एजेंसी

दुनियाभर में घरों के दाम में होने वाली वृद्धि के मामले में जून तिमाही के दौरान तुर्की पहले स्थान पर रहा है, जबकि न्यूजीलैंड दूसरे और अमेरिका तीसरे स्थान पर रहा है। इस सूचकांक में भारत 54वें स्थान पर रहा क्योंकि भारत में जून तिमाही के दौरान आवासों के दाम 0.5 फीसद घटे हैं। आवास मूल्य सूचकांक में भारत दुनिया के 55 देशों में 54वें स्थान पर रहा है। इस दौरान देश में आवासीय संपत्तियों के दाम सालाना आधार पर जून तिमाही में 0.5 फीसद घटे हैं। नाइट फ्रैंक की रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई है।

तुर्की सालाना रैंकिंग में पहले स्थान पर कायम

इससे पहले चालू कैलेंडर वर्ष की पहली तिमाही में भारत वैश्विक आवास मूल्य सूचकांक में 55वें स्थान पर था और अब जून में समाप्त तिमाही में 54वें स्थान पर रहा है। घरों के दाम में 29.2 फीसद की वृद्धि के साथ तुर्की सालाना रैंकिंग में पहले स्थान पर कायम है। न्यूजीलैंड 25.9 फीसद वृद्धि के साथ दूसरे और अमेरिका 18.6 फीसद वृद्धि के साथ तीसरे स्थान पर रहा है।

18 देशों में घरों की कीमतों में 10 फीसद से अधिक की वृद्धि

वैश्विक आवास मूल्य सूचकांक 55 देशों में आवासीय संपत्तियों की कीमतों की निगरानी करता है। चालू कैलेंडर वर्ष की दूसरी तिमाही में 18 देशों में घरों की कीमतों में 10 फीसद से अधिक की वृद्धि हुई। सिर्फ भारत और स्पेन ही ऐसे देश रहे जहां मकान सस्ते हुए। आस्ट्रेलिया में घरों की कीमतों में 16.4 फीसद की वृद्धि हुई। यह 2003 के बाद सबसे ऊंची वृद्धि है।

आगामी तिमाही में घरों की बढ़ेगी मांग

नाइट फ्रैंक इंडिया के चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक शिशिर बैजल ने कहा कि कोविड-19 की दूसरी लहर की वजह से पुनरुद्धार प्रभावित होने के बावजूद भारत में मुख्यधारा की आवासीय इकाइयों के दाम नीचे की ओर झुकाव के साथ लगभग स्थिर रहे। ''कोविड-19 के मामलों में कमी तथा टीकाकरण अभियान की वजह से आगामी तिमाही में घरों की मांग में उल्लेखनीय सुधार की उम्मीद है।

जीएसटी में इनपुट टैक्स क्रेडिट रिफंड मामले में वस्तुओं, सेवाओं को समान नहीं माना जा सकता: न्यायालय

नयी दिल्ली। एजेंसी

उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को एक महत्वपूर्ण फैसले में केंद्र की याचिका को स्वीकार करते हुए कहा कि सीजीएसटी कानून और नियमों के तहत उपयोग नहीं हुये इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) के रिफंड के मामले में वस्तुओं और सेवाओं को समान नहीं माना जा सकता है। न्यायालय ने कहा कि 'रिफंड' मांगना कोई संवैधानिक अधिकार नहीं है बल्कि यह विधि के तहत संचालित है। शीर्ष अदालत ने केंद्रीय माल एवं सेवा कर (सीजीएसटी) कानून की धारा 54 (3) की वैधता को बरकरार रखा। यह धारा उपयोग में नहीं आये आईटीसी की वापसी से जुड़ी है। न्यायालय ने कहा कि न्यायपालिका को कर की दर, रियायात और छूट जैसे मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए क्योंकि यह संसद के अधिकार क्षेत्र के विषय हैं। अगर ऐसा होता है तो इससे विधायी विकल्पों के साथ नीतिगत निर्णयों के मामले में अतिक्रमण होगा जो कार्यपालिका का विशेषाधिकार है। न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायाधीश एम आर शाह की पीठ ने इस मामले से जुड़े गुजरात और मद्रास उच्च न्यायालयों के परस्पर विरोधी निर्णयों पर विभिन्न याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए यह निर्णय सुनाया। दोनों उच्च न्यायालय ने इस बारे में अलग-अलग निर्णय दिये थे कि क्या सीजीएसटी के तहत इनपुट टैक्स क्रेडिट की वापसी के नियम वस्तुओं पर और सेवाओं पर समान रूप से लागू होंगे। शीर्ष अदालत ने गुजरात उच्च न्यायालय के उस फैसले को खारिज कर दिया जिसमें उसने केंद्रीय माल एवं सेवा कर (सीजीएसटी) नियम के नियम 89 (5) को अवैध करार दिया था।

न्यायाधीश चंद्रचूड़ ने 140 पृष्ठ के फैसले को लिखते हुए मद्रास उच्च न्यायालय के निष्कर्षों से सहमति व्यक्त की। उच्च न्यायालय ने नियम की वैधता को बरकरार रखा था। शीर्ष अदालत ने कहा, ''रिफंड का दावा नियमों से संचालित होता है। रिफंड मांगना कोई संवैधानिक अधिकार नहीं है। संसद ने पहले प्रावधान के खंड (ग) में कर भुगतान के बिना शून्य-कर से संबंधित आपूर्ति के मामले में अप्रयुक्त आईटीसी की वापसी की अनुमति दी है। पहले प्रावधान के खंड (ग) के तहत, संसद ने वैसे मामले में अप्रयुक्त आईटीसी की वापसी की परिकल्पना की है, जहां कच्चे माल (इनपुट) पर कर की दर उत्पाद (आउटपुट) आपूर्ति पर कर की दर से अधिक होने के कारण क्रेडिट जमा हुआ है।''

फैसले में कहा गया है, ''जब रिफंड के लिये न कोई संवैधानिक गारंटी है और न ही कानून में इसका अधिकार हो, ऐसे में यह दलील स्वीकार नहीं की जा सकती कि बिना उपयोग वाले आईटीसी की वापसी के मामले में वस्तुओं और सेवाओं को समान रूप से माना जाना चाहिए।''

इस संदर्भ में पूर्व के फैसलों का जिक्र करते हुए न्यायालय ने कहा कि कराधान के क्षेत्र में शीर्ष अदालत ने फार्मूले की व्याख्या के लिये तभी हस्तक्षेप किया है, जब उसका विश्लेषण सही नहीं जान पड़ता है या अव्यवहारिक है।''

न्यायालय ने कहा, ''हालांकि वर्तमान मामले में, फार्मूला अस्पष्ट प्रकृति या अव्यवहारिक नहीं है और न ही यह बिना उपयोग वाले आईटीसी के संचय पर सीमित धनवापसी देने के विधायिका के इरादे का विरोध करता है। हालांकि, शीर्ष अदालत ने इस दलील को स्वीकार किया कि फार्मूले में व्यावहारिक प्रभाव के परिणामस्वरूप कुछ विसंगतियां हो सकती हैं। पीठ ने कहा, ''हमें ऐसे में मामले में विधायिका के अधिकार क्षेत्र में हस्तक्षेप से बचना चाहिए। हालांकि, करदाताओं ने जो विसंगितयां बतायी हैं, हम उसको देखते हुए जीएसटी परिषद से फार्मूले पर पुनर्विचार करते हुये इस सबंध में नीतिगत निर्णय लेने का आग्रह करते हैं।''

स्विगी-जोमैटो से खाना मंगाना हो सकता है महंगा, 17 सितंबर को होगी चर्चा

नई दिल्ली। एजेंसी

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अगुवाई में 17 सितंबर, 2021 को जीएसटी परिषद की 45वीं बैठक होगी। कोरोना काल में कई लोगों ने बाहर रेस्तरां में जाकर खाना खाने के बजाय घर पर खाना ऑर्डर किया। लेकिन अब ऑनलाइन फूड डिलीवरी महंगी हो सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, जीएसटी परिषद इस पर विचार करेगी। कमेटी ने फूड डिलीवरी एप्स को कम से कम पांच फीसदी जीएसटी के दायरे में लाने की सिफारिश की है। ऐसे में ग्राहकों को स्विगी, जोमैटो, आदि से खाना मंगाना महंगा पड़ सकता है।

एक जनवरी 2022 से हो सकता है प्रभावी

2019-20 और 2020-21 में दो हजार करोड़ रुपये के जीएसटी घाटे का अनुमान लगाते हुए, फिटमेंट पैनल ने सिफारिश की है कि फूड एग्रीगेटर्स को ई-कॉमर्स ऑपरेटरों के रूप में वर्गीकृत किया जाए और संबंधित रेस्तरां की ओर से जीएसटी का भुगतान किया जाए। कई रेस्तरां जीएसटी का भुगतान नहीं कर रहे हैं, जबकि कुछ पंजीकृत भी नहीं हैं। रेट फिटमेंट पैनल ने सुझाव दिया है कि यह बदलाव एक जनवरी 2022 से प्रभावी हो सकता है।

पेट्रोलियम पदार्थ भी आ सकते हैं जीएसटी के दायरे में

इसके साथ ही एक या एक से अधिक पेट्रोलियम पदार्थों- पेट्रोल, डीजल, प्राकृतिक गैस और एविएशन टर्बाइन फ्यूल (विमान ईंधन) को भी जीएसटी के दायरे में लाया जा सकता है। केरल हाईकोर्ट की ओर से पेट्रोल व डीजल को जीएसटी के दायरे में लाए जाने के निर्देश के बाद जीएसटी परिषद के समक्ष यह मामला शुक्रवार को लाया जाएगा।

इन मुद्दों पर भी हो सकती है चर्चा

कोरोना वायरस महामारी की आशंकाओं के बीच जीएसटी परिषद की यह 45वीं बैठक बेहद अहम है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस बैठक में अन्य चीजों के अतिरिक्त कोविड-19 से संबंधित आवश्यक सामान पर रियायती दरों की समीक्षा की जा सकती है। इसके साथ ही इस बैठक में राज्यों को राजस्व नुकसान पर मुआवजे पर भी चर्चा हो सकती है। कोविड-19 की दूसरी लहर से आर्थिक गतिविधियां प्रभावित हुई हैं। जनता पर महंगाई का बोझ भी बढ़ा है। ऐसे में वित्त मंत्री की अगुवाई में होने वाली यह बैठक बेहद अहम है।

लगातार दूसरे महीने एक लाख करोड़ के पार रहा ज़ीएसटी संग्रह

मालूम हो कि सरकार का माल एवं सेवा (जीएसटी) संग्रह अगस्त 2021 में 1,12,020 करोड़ रुपये रहा है। वित्त मंत्रालय ने बताया कि अगस्त में 1,12,020 करोड़ रुपये के कुल जीएसटी संग्रह में सकल जीएसटी संग्रह में केंद्रीय जीएसटी (सीजीएसटी) की हिस्सेदारी 20,522 करोड़ रुपये रही, राज्य जीएसटी (एसजीएसटी) की हिस्सेदारी 26,605 करोड़ रुपये रही, एकीकृत जीएसटी (आईजीएसटी) की हिस्सेदारी 56,247 करोड़ रुपये और सेस (Cess) की हिस्सेदारी 8,646 करोड़ रुपये रही।

2021-22 की पहली तिमाही में घरेलू ऋण घटकर 34 प्रतिशत रह सकता है: एसबीआई रिपोर्ट

मुंबई। भारतीय स्टेट बैंक की शोध रिपोर्ट इकोरैप के एक अनुमान के मुताबिक 2021-22 की पहली तिमाही में सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के प्रतिशत के रूप में घरेलू ऋण घटकर 34 प्रतिशत रह सकता है। कोविड-19 महामारी के चलते घरेलू ऋण - जीडीपी दर अनुपात बढ़ गया है। बुधवार को जारी रिपोर्ट के अनुसार यह 2020-21 में तेजी से बढ़कर 37.3 प्रतिशत हो गया, जो 2019-20 में 32.5 प्रतिशत था। शोध रिपोर्ट में कहा गया है, ''हमारा अनुमान है कि वित्त वर्ष 2021-22 की पहली तिमाही में जीडीपी के प्रतिशत के रूप में घरेलू ऋण पहली तिमाही में घटकर 34 प्रतिशत रह गया है, हालांकि निरपेक्ष रूप से यह बढ़ा है।''

रिपोर्ट के मुताबिक निरपेक्ष रूप से वित्त वर्ष 2021-22 की पहली तिमाही में घरेलू ऋण बढ़कर 75 लाख करोड़ रुपये हो गया, जो 2020-21 की पहली तिमाही में 73.59 लाख करोड़ रुपये था। हाल में 2018 के लिए जारी भारत ऋण और निवेश सर्वेक्षण (एआईडीआईएस) रिपोर्ट में कहा गया कि 2012 से 2018 के बीच ग्रामीण और शहरी परिवारों का कर्ज बढ़ा।

हाई कोर्ट बार एसोसिएशन निर्वाचन 2021 2022
अध्यक्ष के लिए तीन एवं उपाध्यक्ष के लिए दो नामांकन फॉर्म

इंदौर। हाई कोर्ट बार एसोसिएशन चुनाव के मुख्य निर्वाचन अधिकारी सीनियर एडवोकेट श्री विनय सराफ एवं सहायक निर्वाचन अधिकारीगण एडवोकेट सर्वश्री अरविंद यादव, मनीष एस. जैन, मिनी रविंद्रन, प्रसन्ना प्रसाद, गौरव छाबड़ा, सुधांशु व्यास, पंकज वाधवानी, हिमांशु जोशी, राजेश खंडेलवाल, आसिफ अहमद खान ने जानकारी देते हुए बताया कि चुनावों में अध्यक्ष पद हेतु मनीष यादव, अनिल ओझा एवं सूरज शर्मा द्वारा नामांकन पत्र प्राप्त किया गया है। वहीं उपाध्यक्ष पद हेतु एमएस चौहान एवं पवन कुमार जोशी द्वारा नामांकन पत्र प्राप्त किए गए। इसी प्रकार सचिव पद के लिए अभिषेक तुगनावत, गौरव श्रीवास्तव एवं मनीष गडकर तथा सचिव पद के लिए निलेश मनोरे, मृदुल भटनागर, आरसी पाटिल, विशाल सनोदिया, एवं सोनल शर्मा द्वारा आवेदन पत्र प्राप्त किए गए हैं।

कार्यकारिणी के 5 पदों के लिए 8 उम्मीदवारों द्वारा नामांकन लिए गए

कार्यकारिणी के 5 पदों के लिए 8 नामांकन पत्र जारी किए गए हैं जिसमें अर्पित यादव, उपेंद्र फणसे, सागर मूले, शैली खत्री, रमेश कुमार अरोरा, ज्ञानेंद्र शर्मा, विराज गोधा एवं जितेंद्र बोहरे द्वारा नामांकन पत्र प्राप्त किए गए हैं।

पोस्टपेड से प्रीपेड सिम के लिए अब KYC जरूरी नहीं

टेलीकॉम सेक्टर के लिए सरकार ने लिए ये बड़े फैसले

नई दिल्ली। एजेंसी

लंबे समय से एजीआर बकाया के संकट से जूझ रही टेलीकॉम इंडस्ट्री के लिए सरकार ने एकसाथ कई अहम ऐलान किए हैं। टेलीकॉम ऑपरेटर को एजीआर चुकाने पर राहत दी गई है तो वहीं 100 फीसदी एफडीआई को भी मंजूरी मिली है। इसके अलावा ग्राहकों को केवाईसी पर भी राहत देने का ऐलान किया गया है। आइए सिलसिलेवार समझते हैं कि केंद्र सरकार की कैबिनेट ने टेलीकॉम इंडस्ट्री और ग्राहकों के हित में कौन से बड़े फैसले लिए हैं।

एजीआर पर क्या हुआः लंबे समय से टेलीकॉम सेक्टर को एडजस्ट ग्रॉस रेवेन्यू यानी एजीआर पर किसी बड़े फैसले का इंतजार था। सरकार ने कहा है कि एजीआर बकाये के परिभाषा में बदलाव किया जाएगा। टेलीकॉम कंपनियां भी इसकी मांग कर रही थीं। वहीं, टेलीकॉम कंपनियों को मंथली इंटरेस्ट रेट को अब एनुअल कर दिया गया है। इसके अलावा पेनल्टी पर भी राहत दी गई है।

यही नहीं, टेलीकॉम ऑपरेटर्स बकाये को लेकर मोरेटोरियम ले सकेंगे। ये 4 साल तक के लिए दिया गया है। जो टेलीकॉम ऑपरेटर ये विकल्प चुनते हैं उन्हें सरकार को ब्याज भी देना होगा। आपको बता दें कि एजीआर की वजह से वोडाफोन-आइडिया और एयरटेल पर भारी वित्तीय बोझ है। इस वजह से कंपनियां काफी संघर्ष कर रही थीं। इसके खिलाफ कंपनियों ने कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाया था।

क्या होता है एजीआरः एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू (एजीआर) एक तरह की यूजेज और लाइसेंसिग फीस है। ये फीस संचार मंत्रालय के दूरसंचार विभाग (ड्ढ्ढ) द्वारा लिया जाता है। दूरसंचार विभाग पिछले कई सालों का बकाया मांग रहा है, जिसे देने में टेलीकॉम कंपनियां आनाकानी कर रह थीं।

आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया है कि टेलीकॉम सेक्टर के ऑटोमेटिक रूट में 100 फीसदी एफडीआई की अनुमति दी गई है।

इसके अलावा टेलीकॉम सेक्टर में अब डिजिटल फॉर्मेट में कस्टमर का वेरिफिकेशन होगा। अभी तक डॉक्युमेंट सब्मिट करना होता था लेकिन सरकार के इस फैसले से ग्राहक अब बिना किसी डॉक्युमेंट की हार्डकॉपी के वेरिफिकेशन करा सकेंगे। आईटी मंत्री ने बताया कि कागजी ग्राहक अधिग्रहण फॉर्म (ढ्ढ्ढ) को डेटा के डिजिटल स्टोरेज से बदल दिया जाएगा।

इसके अलावा ग्राहकों को प्रीपेड से पोस्टपेड में जाने पर दोबारा ख्ष्ण की जरूरत नहीं होगी।

वहीं, टावर के इंस्टॉलेशन के नियम में भी बदलाव हुआ है। सेल्फ डिक्लेरेशन के आधार पर अब ये काम हो सकेगा।

स्पेक्ट्रम नीलामी सामान्यतः प्रत्येक वित्तीय वर्ष की अंतिम तिमाही में आयोजित की जाएगी।

भविष्य की नीलामी में, स्पेक्ट्रम की अवधि 20 से बढ़ाकर 30 वर्ष कर दी गई है, भविष्य में प्राप्त स्पेक्ट्रम के लिए 10 वर्षों के बाद स्पेक्ट्रम के सरेंडर की अनुमति दी जाएगी।

ऑटो सेक्टर को क्या मिलाः मंत्रिमंडल ने भारत की विनिर्माण क्षमताओं को बढ़ाने के लिए ऑटो, ऑटो कलपुर्जा और ड्रोन उद्योग के लिए 26,058 करोड़ रुपये की उत्पादन आधारित प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना को मंजूरी दी। पीएलआई योजना भारत में उन्नत ऑटोमोटिव तकनीक की वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला के विकास को प्रोत्साहित करेगी। इस कदम से 7.6 लाख से अधिक लोगों को अतिरिक्त रोजगार मिलने का अनुमान है।

बेरोजगारी दर सात सप्ताह में सबसे कम हुई, घर-ऑफिस दोनों से काम करना चाहते हैं 86 फीसदी भारतीय

नई दिल्ली। आईपीटी नेटवर्क

देश में बेरोजगारी दर धीरे-धीरे घटने घटने लगी है। सीएमआईई की रिपोर्ट के अनुसार, बेरोजगारी दर 12 सितंबर को खत्म हुए सप्ताह में गिरकर 7.35 फीसदी पर पहुंच गई है। इस साल मई के मुकाबले इसमें 50 फीसदी की की गिरावट आई है। मई में बेरोजगारी दर बढ़कर 14.73 फीसदी के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई थी। रिपोर्ट के अनुसार समीक्षाधीन सप्ताह में शहरी बेरोजगारी दर में मामूली तेजी आई है, जबकि ग्रामीण बेरोगदारी दर में गिरावट आई है। समीक्षाधीन सप्ताह में शहरी बेरोजगारी दर बढ़कर 9.2 फीसदी पर पहुंच गई जो इससे पिछले सप्ताह 8.92 फीसदी थी। रिपोर्ट के मुताबिक हाल के महीनो में जुलाई में बेरोजगारी दर सबसे कम थी। 18 जुलाई को खत्म सप्ताह में बेरोजगारी दर 5.8 फीसदी रही थी। इसके बाद अगस्त में माह के आधार पर बेरोजगारी दर बढ़कर 8.3 फीसदी पर पहुंच गई थी जो जुलाई में सात फीसदी थी।

10 में से नौ भारतीय घर और ऑफिस दोनों जगह करना चाहते हैं काम

प्रोफेशनल और निजी जीवन में बेहतर तालमेल के लिए 10 में से नौ 86 फीसदी भारतीय घर और ऑफिस दोनों हाईब्रिड वर्क जगह से काम करना चाहते हैं। लिंक्डइन के ताजा सर्वे में यह बात कही गई है। इस सर्वे में 1108 लोग शामिल थे। सर्वे के मुताबिक 52 फीसदी ने कहा है कि काम और निजी जीवन के बीच बेहतर तालमेल उतना ही जरूरी है जितना वेतन मायने रखता है। रिपोर्ट के मुताबिक तीन में एक 35 फीसदी ने कहा कि काम काम का बोझ बढ़ा है जबकि 34 फीसदी ने कहा कि काम के बोझ की वजह से तनाव बढ़ा है। 71 फीसदी ने कहा है कि वह ऑफिस जाना इसलिए पसंद कर रहे हैं जिससे अधिकारियों की नजर में उनका काम दिखे। जबकि 89 फीसदी का कहना है कि वह ऑफिस या बाहर इसलिए जाना चाहते हैं जिससे अधिक से अधिक पैसा कमा सकें।

64 फीसदी कंपनियां अक्टूबर-दिसंबर में बंपर भर्तियां करेंगी

3046 कंपनियों पर किए गए सर्वे में सामने आई यह बात

नई दिल्ली। आप नौकरी की तलाश में हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है। इस साल त्योहारी सीजन में सेवा क्षेत्र से लेकर मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र समेत तमाम कंपनियां बंपर भर्तियां करने की तैयारी कर रही हैं। मैनपावर ग्रुप के ताजा सर्वे में यह बात सामने आई है। तीन हजार से अधिक कंपनियों के सर्वे के आधार पर इसमें कहा गया है कि अक्टूबर-दिसंबर के दौरान भर्तियों में पिछली तिमाही के मुकाबले 40 फीसदी का इजाफा होगा जो सात साल का उच्चतम स्तर है।

मांग बढ़ने से भर्तियों में तेजी

रिपोर्ट में कहा गया है कि कोरोना महामारी की वजह से लॉकडाउन हटने और पाबंदियों में ढील से बाजार में मांग बढ़ी है। यह मांग सेवा क्षेत्र के साथ मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में सबसे ज्यादा देखी जा रही है। इसकी वजह से कंपनियां नई भर्तियों की योजना बना रही हैं। सर्वे के मुताबिक सेवा क्षेत्र की 43 फीसदी कंपनियां भर्तियों की तैयारी में हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि मैन्युफैक्चिरंग क्षेत्र में मांग बढ़ने से लॉजिस्टिक क्षेत्र को भी फायदा होगा। इससे अर्थव्यवस्था तेजी से कोरोना संकट से बाहर निकलने में कामयाब हो सकती है।

सर्वे में क्या है खास

कोरोना संकट के दौर में पहली बार 60 फीसदी से अधिक कंपनियों ने भर्तियों की बात कही है। इसमें 64 फीसदी कंपनियों ने कहा है कि वह त्योहारों में भर्तियां करने जा रही हैं। जबकि 15 फीसदी ने कहा है कि वह फिलहाल कोई भर्तियां नहीं करेंगी। वहीं महज 20 फीसदी ने कहा कि वह नौकरियों में कटौती करेंगी। इसमें एक फीसदी कंपनियों ने कहा कि अभी वह कुछ कहने की स्थिति में नहीं हैं।

अर्थव्यवस्था में तेजी के संकेत

सर्वे के मुताबिक इस साल त्योहारों में भर्तियां पिछली तिमाही के मुकाबले 40 फीसदी बढ़ने की उम्मीद है। यह वर्ष 2014 के जुलाई-सितंबर तिमाही के बाद का सबसे ऊंचा है। उस समय 48 फीसदी बढ़ने का अनुमान जताया गया था। विशेषज्ञों का कहना है कि यह अर्थव्यवस्था में बहुत तेज वृद्धि का संकेत है क्योंकि कोरोना संकट की चुनौतियों के बीच कंपनियों में ऐसा उत्साह दिखा है।

पेट्रोलियम, विनिर्मित उत्पादों के दाम बढ़ने से अगस्त में थोक मुद्रास्फीति 11.39 प्रतिशत पर पहुंची

नयी दिल्ली। पेट्रोलियम, विनिर्मित उत्पादों, खनिज तेलों के महंगा होने से अगस्त में थोक मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति मामूली रूप से बढ़कर 11.39 प्रतिशत पर पहुंच गई। हालांकि, इस दौरान खाद्य पदार्थों की कीमतों में नरमी आयी। दो महीने की नरमी को समाप्त करते हुये थोक मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति अगस्त में बढ़ी और लगातार पांचवें महीने दहाई अंक में बनी रही। एक महीना पहले जुलाई में यह 11.16 प्रतिशत और एक साल पहले अगस्त में 0.41 प्रतिशत थी। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने एक बयान में कहा, 'अगस्त 2021 में मुद्रास्फीति के बढ़ने की वजह मुख्य रूप से पिछले साल के इसी महीने के मुकाबले गैर-खाद्य वस्तुओं, खनिज तेलों; कच्चे पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस; मूल धातुओं जैसे विनिर्मित उत्पादों; खाद्य उत्पादों; वस्त्रों; रसायनों और रासायनिक उत्पादों आदि की कीमतों में हुई वृद्धि है।'

खाद्य पदार्थों की यदि बात की जाये तो इस समूह की महंगाई लगातार चौथे महीने कम हुई। जुलाई में शून्य प्रतिशत के मुकाबले अगस्त में यह (-) 1.29 प्रतिशत थी। हालांकि, इस दौरान प्याज और दालों की कीमतों में वृद्धि हुई। प्याज की महंगाई 62.78 प्रतिशत, जबकि दालों की महंगाई 9.41 प्रतिशत बढ़ी। सब्जियों के मामले में इसमें कमी आयी और यह अगस्त में (-) 13.30 प्रतिशत थी।

कच्चे पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस की महंगाई अगस्त में 40.03 प्रतिशत बढ़ गयी। विनिर्मित उत्पादों की महंगाई अगस्त में 11.39 प्रतिशत बढ़ी, जबकि

जुलाई में यह 11.20 प्रतिशत थी। विनिर्मित उत्पादों की महंगाई लगातार चौथे महीने दोहरे अंकों में बनी रही। रिजर्व बैंक ने पिछले महीने अपनी मौद्रिक नीति में ब्याज दरों को रिकॉर्ड निचले स्तर पर अपरिवर्तित रखा था। इसने 2021-22 के दौरान उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) आधारित खुदरा मुद्रास्फीति 5.7 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है, जो इसके पहले के 5.1 प्रतिशत के अनुमान से ज्यादा है। इससे पहले गत शुक्रवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक खुदरा मुद्रास्फीति अगस्त में घटकर चार महीने के सबसे निचले स्तर 5.3 प्रतिशत पर आ गयी, जो इससे पिछले महीने में 5.59 प्रतिशत थी। यह कमी खाद्य वस्तुओं की कीमतों में गिरावट की वजह से हुई।

इक्रा की मुख्य अर्थशास्त्री अदिति नायर ने कहा कि प्रमुख और मूल- थोक मूल्य सूचकांक मुद्रास्फीति अक्टूबर 2021 तक दो अंकों में रहने की उम्मीद है। उसके बाद वर्ष के अंत तक आधी हो जाएगी। अगस्त में आई मामूली बढ़त, अक्टूबर 2021 में मौद्रिक नीति समिति की समीक्षा में यथास्थिति बने रहने के हमारे अनुमान में कोई बदलाव नहीं लाती है। वहीं इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च के प्रधान अर्थशास्त्री सुनील कुमार सिन्हा ने कहा कि आधार प्रभाव के अलावा, अगस्त 2021 की थोक मुद्रास्फीति, ईंधन और ऊर्जा की महंगाई में हुई 26.1 प्रतिशत और विनिर्मित उत्पादों की महंगाई में 11.4 प्रतिशत की वृद्धि से प्रेरित है। ईंधन और ऊर्जा वर्ग में रसोई गैस, पेट्रोल एवं डीजल की महंगाई में क्रमशः 48.1 प्रतिशत, 61.5 प्रतिशत और 50.7 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गयी।

बक्सवाहा के शैल चित्र बंदर हीरा परियोजना से काफी दूर; खनन का कोई प्रभाव नहीं होगा

एजेंसी

हाल के महीनों में बक्सवाहा संरक्षित वन में रॉक पेंटिंग के आसपास कुछ मुद्दे उठे हैं। इस मामले में सबसे पहले तो यह जानना प्रासंगिक है कि इन शैल चित्रों की पहचान पहली बार छत्रसाल महाराजा विश्वविद्यालय, छतरपुर के एक प्रोफेसर (डॉ छारी) ने 2007 में की थी। उनकी रचनाएँ 2016 में बुंदेलखंड जर्नल में प्रकाशित हुई थीं। हालाँकि, ऐसा लगता है कि तब से इस पर कोई और काम नहीं हुआ है।

इस संबंध में एक सबसे महत्वपूर्ण तथ्य जो जानना जरूरी है वो ये कि परियोजना का खनन क्षेत्र इन शैल चित्रों से काफी दूर स्थित है। प्रस्तावित खनन स्थान और निकटतम शैल चित्र स्थल के बीच की दूरी लगभग 10 किलोमीटर से ज्यादा है। गौरतलब है कि हाल के दिनों में इन शैल चित्रों पर प्रस्तावित विकासोन्मुखी बंदर हीरा परियोजना को लेकर कुछ चिंताएँ व्यक्त की गई थीं। साथ ही इस बात को समझने की आवश्यकता है कि आधुनिक उत्खनन और खनन तकनीक में अभूतपूर्व और संवहनीय बदलाव आया है। आधुनिक प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल से धरती के अंदर या उपर ऐसे किसी धरोहरों को नुकसान पहुंचाए बिना विकास के काम किये जा सकते हैं।

देश में ऐसे कई उदाहरण हैं जहां ऐसी परियोजनाएं आधुनिक तकनीक के माध्यम से बड़ी आसानी से पूरी हुईं हैं। उदाहरण के लिए, दिल्ली और मुंबई में मेट्रो रेलवे का निर्माण घनी आबादी वाले क्षेत्रों में जमीन के नीचे किया गया है। वहीं यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल और भी बहुत सारी बिल्डिंग्स है जहां माइनिंग उनके पास हो रही हैं और कोई नुकसान नहीं हुआ है। ये उत्खनन में तकनीकी प्रगति के मजबूत उदाहरण हैं।

दूसरी तरफ ऐसी जानकारी प्राप्त हुईं हैं की बक्सवाहा संरक्षित वन में रॉक पेंटिंग स्मारकों, प्राचीन स्मारकों या पुरातात्विक स्थलों की सूची में नहीं है। इन स्थलों को संरक्षित स्मारकों या राष्ट्रीय महत्व के संरक्षित क्षेत्रों के रूप में वर्गीकृत नहीं किया गया है। यदि इन चित्रों को संरक्षित करने की आवश्यकता है तो प्राचीन स्मारक और पुरातत्व स्थल और अवशेष अधिनियम 1959 (AMASR, 1959) की प्रक्रिया अनुसार इन्हें अधिसूचित किया जाना होगा।

बक्सवाहा रॉक पेंटिंग ना तो भोपाल क्षेत्र के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा घोषित 'केंद्रीय रूप से संरक्षित स्मारक' की सूची, और न ही मध्य प्रदेश राज्य द्वारा घोषित 'संरक्षित स्मारकों' की सूची का हिस्सा है। साथ ही, अभी तक चित्रों के पुरातात्विक और ऐतिहासिक महत्व की पुष्टि नहीं की जा सकी और यह भी कि क्या वे संरक्षित स्मारकों की सूची में शामिल होने के योग्य होंगे या नहीं।

समझने वाली बात यह है कि राष्ट्रीय महत्व के किसी भी प्राचीन स्मारक या पुरातात्विक स्थल को 'संरक्षित क्षेत्र' के रूप में वर्गीकृत किया गया है। ऐसे संरक्षित क्षेत्र से सभी दिशाओं में 100 मीटर का क्षेत्र 'निषिद्ध क्षेत्र' होता है, जबकि निषिद्ध क्षेत्र की सीमा से 200 मीटर दूर एक 'विनियमित क्षेत्र' होता है। किसी भी गतिविधि (निर्माण, खनन, आदि) को ASI की अनुमति के बाद निषिद्ध (संरक्षित क्षेत्र से 100 मीटर तक) और विनियमित क्षेत्रों (संरक्षित क्षेत्र से 300 मीटर तक) में किया जा सकता है। इस प्रकार प्रचलित नियमों के अनुसार, 300 मीटर से अधिक की किसी भी गतिविधि के लिए किसी भी विकासात्मक गतिविधि के लिए किसी अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है। जानकारों का मानना है कि बंदर परियोजना के किसी भी गतिविधि का शैल चित्रों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यह तो तय है की पेंटिंग खदान के नजदीक नहीं हैं और इन पर खनन का कोई प्रभाव नहीं होगा। यदि कभी इन्हे किसी खास धरोहर की सूची में शामिल किया भी जाता है तो बन्दर परियोजना इनको संजोगने का दायित्व ले सकती है।

दूरसंचार पैकेज से दबाव से जूझ रहे क्षेत्र को मिलेगी राहतः उद्योग संगठन सीओएआई

नयी दिल्ली। एजेंसी

दूरसंचार कंपनियों के संगठन सीओएआई (सेल्युलर ऑपरेटर्स एसोसएिश ऑफ इंडिया) ने बुधवार

को घोषित दूरसंचार राहत पैकेज की सराहना करते हुए कहा कि इससे दबाव से जूझ रहे क्षेत्र को बड़ी राहत मिलेगी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दूरसंचार कंपनियों के लिये राहत पैकेज को मंजूरी दी। इसमें अन्य बातों के अलावा समायोजित सकल राजस्व में केवल दूरसंचार सेवाओं से प्राप्त आय को शामिल करने की बात कही गयी है। सीओएआई के महानिदेशक एस पी कोचर ने एक बयान में कहा, ''हम घोषित पैकेज का स्वागत करते हैं। यह हमारी लंबे समय से जारी मांग के अनुरूप है। इससे निश्चित रूप से आने वाले समय में दबाव से जूझ रहे क्षेत्र को राहत मिलेगी।'' कोचर ने कहा कि उद्योग इसे सरकार की सोच के एक संकेतक के रूप में लेता है और 5जी क्रियान्वयन से जुड़ी लागत और प्रक्रियाओं को युक्तिसंगत बनाने का उत्सुकता से इंतजार कर रहा है। उन्होंने कहा कि पैकेज के विस्तार से विश्लेषण के बाद बयान जारी किया जाएगा। के एस लीगल एंड एसोसिएट्स की प्रबंध भागीदार सोनम चांदवानी ने कहा, ''इससे वोडाफोन आइडिया जैसी संकट में फंसी दूरसंचार कंपनी को राहत मिलेगी। क्योंकि ऐसा नहीं होने पर पिछले सांविधिक बकाया को लेकर करोड़ों रुपये देने पड़ते। देनदारी को कुछ समय के लिये टाला गया है, इसे पूरी तरह से बट्टे खाते में नहीं डाला गया है।'' उन्होंने कहा कि इससे बैंकों को भी राहत मिलेगी क्योंकि उनके वोडाफोन आइडिया पर काफी राशि बकाया है। ''हालांकि अभी साफ नहीं है कि वोडाफोन कैसे बकाये का भुगतान करेगी, लेकिन अतिरिक्त समय मिलने से निश्चित रूप से उन्हें दबाव प्रबंधन में मदद मिलेगी।'' चांदवानी ने यह भी कहा, ''राहत समय पर आयी है और दूरसंचार कंपनियों को इससे मदद मिलेगी। देनदारी को टाला गया है, समाप्त नहीं किया गया है। वोडाफोन की गंभीर वित्तीय स्थिति को देखते हुए, यह अभी साफ नहीं है कि कैसे वह कर्ज का भुगतान करेगी तथा कारोबार को कैसे व्यावहारिक बनाएगी।''

शेयर बाजार में लौटी रौनक, सेंसेक्स को मिली नई ऊंचाई, निफ्टी की भी रिकॉर्ड क्लोजिंग

मुंबई। आईपीटी नेटवर्क

सप्ताह के तीसरे कारोबारी दिन यानी बुधवार को भारतीय शेयर बाजार में कई नए रिकॉर्ड बने। सेंसेक्स 476.11 अंक या 0.82 फीसदी की तेजी के साथ 58,723.20 अंक पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 139.45 अंक या 0.80इ ऊपर 17,519.45 पर बंद हुआ। ये सेंसेक्स और निफ्टी की रिकॉर्ड क्लोजिंग है। इससे पहले, कारोबार के दौरान सेंसेक्स ने 58777.06 अंक तक के स्तर को टच कर लिया। ये सेंसेक्स का ऑल टाइम हाई लेवल है।

टेलीकॉम और ऑटो सेक्टर को बूस्टः राहत पैकेज की उम्मीदों की वजह से ऑटो और टेलीकॉम सेक्टर के शेयर में तेजी रही। एयरटेल का शेयर करीब 5 फीसदी की तेजी के साथ बंद हुआ। इसी के साथ एयरटेल का मार्केट कैपिटल भी 4 लाख करोड़ रुपए के स्तर को पार कर लिया है। बीएसई इंडेक्स पर अन्य शेयरों की बात करें तो एनटीपीसी, एचसीएल, टाइटन, एसबीआईएन, पावरग्रिड, टीसीएस, इंडसइंड बैंक, इन्फोसिस और एलएंडटी शामिल हैं। एक्सिस बैंक, अल्ट्राटेक, एशियन पेंट, नेस्ले, सनफार्मा टॉप लूजर में शामिल हैं।

मंगलवार को बाजार का हालः बीएसई इंडेक्स की बात करें तो सेंसेक्स 69.33 अंक यानी 0.12 प्रतिशत की बढ़त के साथ 58,247.09 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 24.70 अंक यानी 0.14 प्रतिशत की तेजी के साथ 17,380 अंक की रिकॉर्ड ऊंचाई पर बंद हुआ। 60 हजारी बनने के करीबः शेयर बाजार की मौजूदा रिकवरी को देखकर ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि आने वाले सप्ताह में सेंसेक्स 60 हजार अंक के स्तर को टच कर लेगा। आपको बता दें कि अगस्त के पहले सप्ताह में ही सेंसेक्स ने 58 हजार अंक के स्तर को टच किया था।

अदाणी ट्रांसमिशन 1,200 करोड़ रुपये के कैपेक्स के साथ मध्य प्रदेश में पावर ट्रांसमिशन सिस्टम को मजबूती प्रदान करेगा

अहमदाबाद। आईपीटी नेटवर्क

भारत की सबसे बड़ी निजी क्षेत्र की पावर ट्रांसमिशन कंपनी, अदाणी ट्रांसमिशन लिमिटेड (एटीएल)डायवर्सिफाइड अदाणीग्रुप का हिस्सा है। एटीएलको आरईसी पावर डेवलपमेंट एंड कंसल्टेंसी लिमिटेड द्वारा निगमित, एमपी पावर ट्रांसमिशन पैकेज-छ्छ लिमिटेड के अधिग्रहण के लिए आशय पत्र (एलओआई) प्राप्त हुआ है। एटीएल ने टैरिफ-आधारित प्रतिस्पर्धी बोली (टीबीसीबी) प्रक्रिया के जरिये परियोजना हासिल की और 14 सितंबर 2021 को एलओआई प्राप्त किया। एटीएल 35 वर्षों की अवधि के लिए मध्य प्रदेश में ट्रांसमिशन परियोजना का निर्माण करेगा, स्वामित्व रखेगा, तथा उसका संचालन और रखरखाव करेगा। 'एमपी पावर ट्रांसमिशन पैकेज-छ्छ लिमिटेड' परियोजनामें मध्य प्रदेश के 18 जिलों में लगभग 850 सीकेटी किमी ट्रांसमिशन लाइनें और विभिन्न वोल्टेज स्तरों (220 केवी और 132 केवी) के एयर इंसुलेटेड सबस्टेशन शामिल हैं। 1,200 करोड़ रुपये के पूंजीगत व्यय (कैपेक्स) के साथ, एटीएल की परियोजना के कार्यान्वयन से पूर्वी मध्य प्रदेश में ट्रांसमिशन सिस्टम को मजबूती मिलेगी। अदाणी ट्रांसमिशन लिमिटेड के एमडी एवं सीईओ श्री अनिल सरदाना ने बताया कि'प्राइवेट सेक्टर के पावर ट्रांसमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण में अग्रणी भूमिका निभाते हुए, हम प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के माध्यम से अपनी अखिल भारतीय उपस्थिति को बढ़ाने में तेजी ला रहे हैं और सर्वोत्तम सस्टेनेबल प्रथाओं में इंडस्ट्रियल बेंचमार्क्स को भी स्थापित कर रहे हैं। इस नवीनतम परियोजना के जरिये हम मध्य प्रदेश में ट्रांसमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देने की स्थिति में रहेंगे।' इस परियोजना को हासिल करके, भारत की सबसे बड़ी ऑपरेटिंग प्राइवेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी के रूप में एटीएल की स्थिति मजबूत हुई है और एटीएल को 2022 तक 20,000 सीकेटी किमी ट्रांसमिशन लाइनें स्थापित करने के अपने लक्ष्य के करीब ले जाती है। इस परियोजना के जरिये कंपनी 2022 तक सभी के लिए बिजलीउपलब्ध कराने केभारत सरकारके प्रयास में भी सहायता कर पायेगी।

श्री गणेश को इस विसर्जन मंत्र से करें बिदा, मिलेगा खुशियों का आशीष सदा

गणेशोत्सव का पर्व गणेश चतुर्थी से शुरू होकर 10 दिनों तक चलता है और अनंत चतुर्दशी के दिन समाप्त होता है। अनंत चतुर्दशी के ही दिन श्री गणेश विसर्जन भी होता है अर्थात 19 सितंबर 2021, रविवार के दिन होगा। इस दिन श्री गणेश विसर्जन से पूर्व स्थापित श्री गणेश प्रतिमा का संकल्प मंत्र के बाद षोड़शोपचार पूजन-आरती करना चाहिए। गणेश जी की मूर्ति पर सिंदूर चढ़ाएं। मंत्र बोलते हुए 21 दूर्वा-दल चढ़ाएं। 21 लड्डुओं का भोग लगाएं। इनमें से 5 लड्डू मूर्ति के पास चढ़ाएं और 5 ब्राह्मण को प्रदान कर दें। शेष लड्डू प्रसाद के रूप में बांट दें।

पूजन के समय यह मंत्र बोलें- ॐ गं गणपतये नमः

दूर्वा-दल चढ़ाते समय यह मंत्र बोलें- श्री गणेश को 21 दूर्वा-दल चढ़ाई जाती है। दो दूर्वा-दल नीचे लिखे नाम मंत्रों के साथ चढ़ाएं।

ॐ गणाधिपाय नमः
ॐ उमापुत्राय नमः
ॐ विघ्ननाशनाय नमः
ॐ विनायकाय नमः
ॐ ईशपुत्राय नमः
ॐ सर्वसिद्धप्रदाय नमः
ॐ एकदन्ताय नमः
ॐ इभवक्त्राय नमः
ॐ मूषकवाहनाय नमः
ॐ कुमारगुरवे नमः

इसके बाद श्री गणेश की आरती करें और विसर्जन स्थल पर ले जाकर पुनः एक बार आरती करें एवं श्री गणेश की प्रतिमा जल में विसर्जित कर दें और यह मंत्र बोलें-

यान्तु देवगणाः सर्वे पूजामादाय मामकीम् ।
इष्टकामसमृद्धयर्थं पुनर्अपि पुनरागमनाय च?

धर्मग्रंथों में उल्लेख है कि इस दौरान यदि नदी या तालाब से थोड़ा जल लेकर गणेश प्रतिमा पर चढ़ा दिया जाए तो यह विधिवत विसर्जन ही माना जाएगा।

डोल ग्यारस कब है, जानिए पूजा के शुभ मुहूर्त, महत्व और क्या करते हैं इस दिन

भाद्रपद में शुक्ल पक्ष की एकादशी को परिवर्तनी एकादशी कहते हैं। इसके अलावा इसे जलझूलनी यानी डोल ग्यारस भी कहते हैं। इस बार यह एकादशी 17 सितंबर शुक्रवार को रहेगी।

डोल ग्यारस का महत्व : इस दिन भगवान विष्णु करवट बदलते हैं। इसीलिए इसे परिवर्तिनी एकादशी कहते हैं। परिवर्तिनी एकादशी के व्रत से सभी दुःख दूर होकर मुक्ति मिलती है। इस दिन को व्रत करने से वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है। इस दिन भगवान कृष्ण के बाल रूप का जलवा पूजन किया गया था। इसीलिए इसे डोल ग्यारस कहा जाता है। इसी दिन राजा बलि से भगवान विष्णु ने वामन रूप में उनका सर्वस्व दान में मांग लिया था एवं उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर अपनी एक प्रतिमा को राजा बलि को सौंप दी थी, इसी वजह से इसे वामन ग्यारस भी कहा जाता है।

क्यों कहते हैं डोल ग्यारस : इस दिन भगवान कृष्ण के बालरूप बालमुकुंद को एक डोल में विराजमान करके उनकी शोभा यात्रा निकाली जाती है। इसीलिए इसे डोल ग्यारस भी कहा जाने लगा।

क्या होता है इस दिन : डोल ग्यारस के अवसर पर सभी कृष्ण मंदिरों में पूजा-अर्चना होती है। भगवान कृष्ण की मूर्ति को एक डोल में विराजमान कर उनको नगर भ्रमण कराया जाता है। इस अवसर पर कई शहरों में मेले, चल समारोह, अखाड़ों का प्रदर्शन और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी होता है। इसके साथ ही डोल ग्यारस पर भगवान राधा-कृष्ण के एक से बढ़कर एक नयनाभिराम विद्युत सज्जित डोल निकाले जाते हैं।

क्यों मनाते हैं डोल ग्यारस : श्रीकृष्ण जन्म के 16वें दिन माता यशोदा ने उनका जलवा पूजन किया था। इसी दिन को 'डोल ग्यारस' के रूप में मनाया जाता है। जलवा पूजन के बाद ही संस्कारों की शुरुआत होती है। जलवा पूजन को कुआं पूजन भी कहा जाता है।

पूजा के मुहूर्त : इस दिन श्रावण नक्षत्र रहेगा। 11:28 AM से 12:17 PM तक अभिजीत मुहूर्त रहेगा। 05:26 इश से 07:00 इश तक अमृत काल रहेगा। 05:48 PM से 06:12 PM तक गोधूलि मुहूर्त रहेगा। 05:45 AM से 08:07 AM तक भद्रा काल रहेगा जिसमें पूजन नहीं होता है। 17 सितंबर 05:45 AM से 18 सितंबर 03:36 AM तक सर्वार्थ सिद्धि योग रहेगा।

कैसे मनाते हैं डोल ग्यारस : इस व्रत में धूप, दीप, नैवेद्य और पुष्प आदि से पूजा करने की विधि-विधान है। सात कुंभ स्थापित किए जाते हैं। सातों कुंभों में सात प्रकार के अलग-अलग धान्य भरे जाते हैं। इन सात अनाजों में गेहूं, उडद, मूंग, चना, जौ, चावल और मसूर है। एकादशी तिथि से पूर्व की तिथि अर्थात दशमी तिथि के दिन इनमें से किसी धान्य का सेवन नहीं करना चाहिए।

कुंभ के ऊपर श्री विष्णु जी की मूर्ति रख पूजा की जाती है। इस व्रत को करने के बाद रात्रि में श्री विष्णु जी के पाठ का जागरण करना चाहिए यह व्रत दशमी तिथि से शुरु होकर, द्वादशी तिथि तक जाता है। इसलिए इस व्रत की अवधि सामान्य व्रतों की तुलना में कुछ लंबी होती है। एकादशी तिथि के दिन पूरे दिन व्रत कर अगले दिन द्वादशी तिथि के प्रातःकाल में अन्न से भरा घड़ा ब्राह्मण को दान में दिया जाता है।

गणपति जी की 4 भुजाओं के 4 रहस्य

वैसे जो गणेशजी की दो भुजाएं हैं परंतु विशेषावतार के समय उन्हें चार भुजाधारी बताया गया है। उनकी चारों भुजाओं के चारों हाथों में चार वस्तुएं होती हैं। उनकी चार भुजाओं में से एक हाथ में अंकुश, दूसरे हाथ में पाश, तीसरे हाथ में मोदक व चौथे में आशीर्वाद है। आओ जानते हैं कि उनकी चार भुजाओं का क्या है रहस्य।

1. पहली भुजा : उनके पहले हाथ में अंकुश इस बात का सूचक है कि कामनाओं पर संयम जरूरी है।

2.दूसरी भुजा : उनकी दूसरी भुजा में पाश इस बात का सूचक है कि हर व्यक्ति को स्वयं के आचरण और व्यवहार में इतना संयम और नियंत्रण रखना जरूरी है, जिससे जीवन का संतुलन बना रहे। पाश नियंत्रण, सयंम और दण्ड का प्रतीक है।

3.तीसरी भुजा : उनकी तीसरी भुजा में मोदक होता है। मोदक का अर्थ जो मोद (आनन्द) देता है, जिससे आनन्द प्राप्त हो, संतोष हो। तन और मन में संतोष होना जरूरी है, तभी आप जीवन का वास्तविक आनंद पा सकते हैं। कैसे आता है संतोष? दरअसल, जैसे मोदक को थोड़ा-थोड़ा और धीरे-धीरे खाने पर उसका स्वाद और मिठास अधिक आनंद देती है और अंत में मोदक खत्म होने पर आप तृप्त हो जाते हैं, उसी तरह वैसे ही ऊपरी और बाहरी ज्ञान व्यक्ति को आनंद नहीं देता परंतु ज्ञान की गहराई में सुख और सफलता की मिठास छुपी होती है।

4.चौथी भुजा : इस भुजा से वह भक्तों को आशीर्वाद देते हैं। जो अपने कर्म के फलरूपी मोदक भगवान के हाथ में रख देता है, उसे प्रभु आशीर्वाद देते हैं। यही चौथे हाथ का संदेश है।

अनंत चतुर्दशी पर करें भगवान अनंत की इस तरह पूजा, मिलेगा ये चमत्कारिक लाभ

भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी से 10 दिवसीय गणेश चतुर्थी उत्सव की शुरुआत होती है जो अनंत चतुर्दशी तक चलती है। इस बार गणेश उत्सव की शुरुआत 10 सितंबर से होगी और 19 सितंबर को अंत चतुर्दशक्ष का व्रत रखा जाएगी। आओ जानते हैं अनंत चतुर्दशी के व्रत के संबंध में खास जानकारी।

1. विष्णु की पूजा : अनंत चतुर्दशी के दिन भगवान अनंत (विष्णु) की पूजा का विधान होता है। अग्नि पुराण में अनंत चतुर्दशी व्रत के महत्व का वर्णन मिलता है।

2. अनंत सूत्र : इस दिन अनंत सूत्र बांधने का विशेष महत्व होता है। इस व्रत में भगवान विष्णु के अनंत रूप की पूजा के बाद बाजू पर अनंत सूत्र बांधा जाता है।

3. अनंत चतुर्दशी का महत्व : भगवान श्रीकृष्ण ने पांडवों द्वारा जुए में अपना राजपाट हार जाने के बाद श्रीकृष्ण से पूछा था कि दोबारा राजपाट प्राप्त हो और इस कष्ट से छुटकारा मिले इसका उपाय बताएं तो श्रीकृष्ण ने उन्हें सपरिवार सहित अनंत चतुर्दशी का व्रत बताया था।

4. क्यों कहलाते हैं अनंत : चतुर्मास में भगवान विष्णु शेषनाग की शैय्या पर अनंत शयन में रहते हैं। अनंत भगवान ने ही वामन अवतार में दो पग में ही तीनों लोकों को नाप लिया था। इनके ना तो आदि का पता है न अंत का इसलिए भी यह अनंत कहलाते हैं अतः इनके पूजन से आपके सभी कष्ट समाप्त हो जाएंगे। भगवान विष्णु के सेवक भगवान शेषनाग का नाम अनंत है।

5. कैसे करें पूजा : प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर व्रत का संकल्प लेकर पूजा स्थल पर कलश स्थापित किया जाता है। कलश पर अष्टदल कमल की तरह बने बर्तन में कुश से निर्मित अनंत की स्थापना करने के पश्चात एक धागे को कुमकुम, केसर और हल्दी से रंगकर अनंत सूत्र तैयार करें, इसमें चौदह गांठें लगी होनी चाहिए। इसे भगवान विष्णु की तस्वीर के सामने रखकर भगवान विष्णु और अनंत सूत्र की षोडशोपचार विधि से पूजा शुरू करें और नीचे दिए गए मंत्र का जाप करें। इसके बाद विधिवत पूजन के बाद अनंत सूत्र को बाजू में बांध लें। पुरुष दांये हाथ में और महिलाएं बांये हाथ में बांधे।

अनंत संसार महासुमद्रे मग्नं समभ्युद्धर वासुदेव।
अनंतरूपे विनियोजयस्व ह्यानंतसूत्राय नमो नमस्ते॥

मान्यता है कि इस दिन व्रत रखने के साथ-साथ यदि कोई व्यक्ति श्री विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ करता है, तो उसकी समस्त मनोकामना पूर्ण होती है। धन-धान्य, सुख-संपदा और संतान आदि की कामना से यह व्रत किया जाता है।

खाने के तेल के दाम आगे भी बढ़ने की आशंका

ज्यादा बारिश होने से घट सकती है पैदावार

नई दिल्ली। एजेंसी

इस साल खरीफ की फसल में कई चीजों की बुवाई बेहतर हुई है तो तिलहन में कमी देखी जा रही है। विशेषज्ञों के मुताबिक अगर मॉनसून लंबा खिंचा तो अच्छी बुवाई के बावजूद ज्यादा बारिश होने से पैदावार घट सकती है। ऐसा हुआ तो महंगाई का और बढ़ना तय है। केयर रेटिंग के मुताबिक 10 सितंबर तक के आंकड़ों के हिसाब से पिछले साल के 1107 लाख हेक्टेयर के मुकाबले अभी तक 1097 लाख हेक्टेयर ही बुवाई हो पाई है। इसमें एमएसपी बढ़ने का असर भी दिख रहा है। धान की फसल 1.6 हेक्टेयर, दलहन की फसल 2.66 हेक्टेयर ज्यादा बोई गई है। दलहन की ज्यादा बुआई से मूंग, अरहर और उड़द की दाल का उत्पादन बढ़ने की उम्मीद है। इसके अलावा गन्ने की बुआई भी 0.74 लाख हेक्टेयर ज्यादा देखी गई है।

मूंगफली की बुआई 3.2 लाख हेक्टेयर घटी

इसके अलावा मोटे अनाज की बात की जाए को इनका रकबा 4.42 लाख हेक्टेयर घटा है। इसमें बाजरे की फसल की बुआई घटी है। साथ ही कपास का रकबा 7.3 लाख हेक्टेयर घटा है। इससे टेक्सटाइल उद्योग का कच्चामाल महंगा होने की आशंका है। तिलहन की बात की जाए तो मूंगफली की बुआई 3.2 लाख हेक्टेयर घटी है। सोयाबीन की फसल जरूर लक्ष्य के हिसाब से है। देश में जिस हिसाब से 55-60 फीसदी खाने का तेल आयात किया जाता है मूंगफली का कम उत्पादन मुश्किल पैदा कर सकता है।केयर रेटिंग के मुख्य अर्थशास्त्री मदन सबनविस ने बताया है कि तिलहन और दलहन के मोर्चे पर अगर बुवाई के मुकाबले पैदावार घटती है तो आयात बढ़ेगा ही ऐसे में इन चीजों की महंगाई बढ़नी तय है। वहीं चावल या फिर दलहन की बात की जाए तो अभी तक बुवाई कम है। चावल का बफर स्टॉक पर्याप्त मात्रा में देश में मौजूद है। अगर इसकी उपज घटती है तो इसके आयात की जरूरत नहीं होगी। वहीं दलहन में यदि उपज घटी तो आयात बढ़ेगा।

सबसे ज्यादा असर खाने पीने की चीजों की कीमतों पर

उन्होंने ये भी बताया कि बुवाई अच्छी होने के बावजूद अगर मॉनसून ज्यादा दिनों तक टिका तो फसल बर्बाद होने की पूरी आशंका बनी हुई है। पिछले साल भी अक्टूबर के आखिर तक मॉनसून का असर देखा गया था ऐसे में इन फसलों की कटाई के समय मुश्किल आई। ऐसे हालातों का सबसे ज्यादा असर खाने पीने की चीजों की कीमतों पर देखने को मिलेगा, जो महंगाई बढ़ाएगा।

मध्यप्रदेश में 11,311 करोड़ रुपये की सड़क परियोजनाओं का शिलान्यास, लोकार्पण करेंगे गडकरी

इंदौर। आईपीटी नेटवर्क

केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी 16 सितंबर को मध्यप्रदेश में कुल 11,311 करोड़ रुपये की लागत वाली 35 सड़क परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। मध्यप्रदेश सरकार के अधिकारियों ने मंगलवार को बताया कि ये परियोजनाएं राज्य में 1,530 किलोमीटर लंबी सड़कों के निर्माण से संबंधित हैं। उन्होंने बताया कि इंदौर में आयोजित कार्यक्रम के दौरान गडकरी राज्य में सड़क निर्माण की 21 परियोजनाओं का शिलान्यास और 14 परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे। इस कार्यक्रम में राज्य के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद रहेंगे। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) के अधिकारियों ने बताया कि इंदौर के इस कार्यक्रम से पहले, गडकरी आठ लेन वाले दिल्ली-वड़ोदरा-मुंबई एक्सप्रेस-वे के राज्य से होकर गुजरने वाले करीब 245 किलोमीटर लम्बे हिस्से के जारी निर्माण कार्य का बृहस्पतिवार को रतलाम जिले में निरीक्षण करेंगे। अधिकारियों के मुताबिक इस हिस्से के निर्माण पर करीब 8,437 करोड़ रुपये की लागत आने का अनुमान है। उन्होंने बताया कि दिल्ली-वड़ोदरा-मुंबई एक्सप्रेस-वे के तहत बनाई जा रही आठ लेन की सड़क पश्चिमी मध्यप्रदेश के मंदसौर जिले में 102.4 किलोमीटर, रतलाम जिले में 90.1 किलोमीटर और झाबुआ जिले में 52 किलोमीटर गुजरेगी। अधिकारियों ने बताया कि राज्य में इस परियोजना के तहत प्रस्तावित कुल 245 किलोमीटर में से 106 किलोमीटर लम्बी सड़क बनाई जा चुकी है और बाकी काम पूरा करने के लिए नवंबर 2022 की समय-सीमा तय की गई है।

दालों की बढ़ती किमतों से आम आदमी को राहत देने की तैयारी

नई दिल्ली। एजेंसी

विदेश राज्यमंत्री वी मुरलीधरन ने मंगलवार को कहा कि भारत ने दाल की घरेलू जरूरतों को पूरा करने के लिये इसके आयात को लेकर मलावी और मोजाम्बिक के साथ समझौते किए हैं। इसके अलावा कुछ अन्य अफ्रीकी देशों के साथ भी दाल आयात को लेकर बातचीत चल रही है। भारत-अफ्रीका कृषि और खाद्य प्रसंस्करण शिखर सम्मेलन 2021 के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि अफ्रीका के लिए भारत चौथा सबसे बड़ा व्यापार भागीदार है और पांचवां सबसे बड़ा निवेशक बन गया है। भारत का कुल निवेश अफ्रीका में 70.7 अरब डॉलर है। मुरलीधरन ने यह भी कहा कि अफ्रीका के साथ भारत आर्थिक और वाणिज्यिक संबंधों को और मजबूत बनाने को लेकर संभावनाएं टटोल सकता है। उन्होंने कहा कि खाद्य सुरक्षा भारत और अफ्रीका को जोड़ती है। भारत ने मानवीय सहायता के रूप में विभिन्न अफ्रीकी देशों को 1.58 करोड़ डॉलर की खाद्य सहायता उपलब्ध कराई है। मुरलीधरन ने कहा, ''भारत ने घरेलू मांग को पूरा करने के लिए दाल आयात को लेकर मलावी और मोजाम्बिक के साथ समझौते किए हैं। फिलहाल हम दाल के आयात को लेकर कुछ और अफ्रीकी देशों के साथ समझौता ज्ञापन पर बातचीत कर रहे हैं।

भारत दाल का सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता

भारत दाल का सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता देश है। उन्होंने कहा कि अफ्रीका के पास काफी भूमि है, जिसे वह विभिन्न उत्पादों के उत्पादन के लिये उपलब्ध करा सकता है। मंत्री ने कहा, ''भारत बड़े पैमाने पर रोजगार और आय पैदा करने के साथ कृषि-प्रसंस्करण सुविधाओं के निर्माण के माध्यम से.... विदेशों में निवेश करने और फसलों का उत्पादन करने का अवसर तलाशना चाहता है। उन्होंने कहा कि निजी क्षेत्र की कंपनियां पहले ही कई अफ्रीकी देशों में इस क्षेत्र में निवेश करना शुरू कर चुकी हैं। उन्होंने कहा, ''अफ्रीकी महाद्वीपीय मुक्त व्यापार क्षेत्र (एएफसीएफटीए) एक जनवरी, 2021 में अमल में आया है। इसके पूरे अफ्रीका में कृषि विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की उम्मीद है। मंत्री ने कहा कि कोविड-19 महामारी ने अफ्रीकी देशों समेत दुनिया की वृद्धि को प्रभावित किया है।

किसानों के लिए घाटे का सौदा साबित हो रही मिर्च की खेती, तुड़वाने की लागत निकालना भी मुश्किल

इंदौर। एजेंसी

मिर्च की खेती किसानों के लिए घाटे का सौदा साबित हो रही है, क्योंकि मध्य प्रदेश में अधिक उत्पादन के चलते इस मसाला फसल के थोक दाम इस कदर गिर गए हैं कि उनके लिए इसके उत्पादन और इसे खेत से तुड़वाने की लागत निकालना मुश्किल हो रहा है। राज्य के सबसे बड़े मिर्च उत्पादक निमाड़ अंचल के खरगोन जिले के गजानंद यादव इन किसानों में शामिल हैं, जिन्होंने पांच एकड़ में मिर्च बोई है।

एक किलोग्राम मिर्च उगाने में करीब आठ रुपये की लागत

उन्होंने बताया, 'इस वक्त हरी मिर्च का थोक मूल्य 11 से 12 रुपये प्रति किलोग्राम के बीच चल रहा है, जबकि हमें एक किलोग्राम मिर्च उगाने में करीब आठ रुपये की लागत आती है और मजदूर इसे खेत से तोड़ने के बदले पांच

रुपये किलोग्राम के मान से मेहनताना लेते हैं।' यादव ने बताया कि पिछले साल किसानों को एक किलोग्राम हरी मिर्च के बदले 42 रुपये तक का ऊंचा दाम मिला था और इसे देखते हुए वर्तमान सत्र में इसकी खेती के प्रति उनका आकर्षण बढ़ गया।

ज्यादा उत्पादन होने से दाम गिरे

उद्यानिकी विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि राज्य में हरी मिर्च का ज्यादा उत्पादन होने से इसके थोक दाम गिर गए हैं, लेकिन आने वाले दिनों में जब यह सूख कर लाल हो जाएगी तो किसानों को इसका बेहतर मोल मिलने की उम्मीद है। पश्चिमी मध्यप्रदेश के निमाड़ अंचल की गिनती देश के प्रमुख मिर्च उत्पादक क्षेत्रों में होती है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक सूबे में फिलहाल सालाना मिर्च उत्पादन करीब 2.18 लाख टन के स्तर पर है। इसमें निमाड़ अंचल के पांच जिलों-खरगोन, धार, खंडवा, बड़वानी और अलीराजपुर का 54,451 टन मिर्च उत्पादन शामिल है। यानी सूबे के कुल मिर्च उत्पादन में अकेले निमाड़ अंचल की भागीदारी 25 प्रतिशत है।

ओला ई-स्कूटर की बिक्री शुरू, EMI पर खरीदने का यह है तरीका

नई दिल्ली। 15 सितंबर से ओला के इलेक्ट्रिक स्कूटर की बिक्री शुरू हो रही है। जिन ग्राहकों ने प्री-बुकिंग में कंपनी का ई-स्कूटर बुक कराया है, वे बाकी पेमेंट कर इसे खरीद सकते हैं। कंपनी के सीईओ भाविष अग्रवाल ने ट्विटर पर बिक्री शुरू होने की जानकारी दी है। कंपनी पिछले हफ्ते बिक्री शुरू करने वाली थी, लेकिन उसकी वेबसाइट में कुछ तकनीकी दिक्कतों की वजह से इसे टाल दिया गया था।

अगर आपने ओल ई-स्कूटर बुक कराया है तो आप बाकी रकम का भुगतान कर या बैंक से लोन लेकर इसे खरीद सकते हैं। कंपनी के ई-स्कूटर के दो वेरिएंट्स हैं-ए1 और ए1 ईद। एस1 वेरिएंट की कीमत 99,999 रुपये और एस1 प्रो की कीमत 1,29,999 रुपये है। दिल्ली में राज्य सरकार की तरफ से मिलने वाली सब्सिडी (एलेंब्) के बाद एस1 की कीमत 85,009 रुपये पड़ेगी। गुजरात में सब्सिडी के बाद इसकी कीमत 79,000 रुपये पड़ेगी।

ओला ई-स्कूटर ऑनलाइन खरीदने के लिए आपको कंपनी की वेबसाइट पर जाना होगा। वहां आपको एक बार में पूरा पमेंट करने यह फाइनेंस ऑप्शन चुनने का विकल्प मिलेगा। अगर आप लोन लेकर इसे खरीदना चाहते हैं तो आपको बैंक ऑफ बड़ौदा, एक्सि बैंक, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, जना स्मॉल फाइनेंस बैंक, कोटक महिंद्रा प्राइम, टाटा कैपिचल और यस बैंक में से किसी एक चुनाव करना होगा। ओला ने फाइनेंस स्कीम के लिए उपर्युक्त बैंकों से समझौता किया है। एस1 की न्यूनतम ईएमआई 2,999 रुपये से शुरू होती है, जबकि एस1 प्रो की ईएमआई 3,199 रुपये से शुरू होती है। आपको 48 महीनों में लोन की रकम को चुकाना होगा। हालांकि, बैंकों की लोन की स्कीम के आधार पर ईएमआई की रकम में बदलाव हो सकता है। ओला इलेक्ट्रिक के ब्लॉग में कहा गया है कि एचडीएफसी बैंक ओला और ओला इलेक्ट्रिक एप पर एलिजेबल कस्टमर्स को कुछ ही मिनटों में प्री-अप्रूव्ड लोन दे देगा। टाटा कैपिटल और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक डिजिटल प्रोसेस के बाद तुरंत लोन एप्रूव कर देंगे। इसके लिए आधार कार्ड, पैन कार्ड और एड्रेस प्रूफ की जरूरत पड़ेगी।

भारत दाल आयात के लिये अफ्रीकी देशों के साथ कर रहा बातचीतः मंत्री

नयी दिल्ली। विदेश राज्यमंत्री वी मुरलीधरन ने मंगलवार को कहा कि भारत ने दाल की घरेलू जरूरतों को पूरा करने के लिये इसके आयात को लेकर मलावी और मोजाम्बिक के साथ समझौते किये हैं। इसके अलावा कुछ अन्य अफ्रीकी देशों के साथ भी दाल आयात को लेकर बातचीत चल रही है। भारत-अफ्रीका कृषि और खाद्य प्रसंस्करण शिखर सम्मेलन 2021 के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि अफ्रीका के लिये भारत चौथा सबसे बड़ा व्यापार भागीदार है और पांचवां सबसे बड़ा निवेशक बन गया है। भारत का कुल निवेश अफ्रीका में 70.7 अरब डॉलर है। मंत्री ने यह भी कहा कि अफ्रीका के साथ भारत आर्थिक और वाणिज्यिक संबंधों को और मजबूत बनाने को लेकर संभावनाएं टटोल सकता हे। उन्होंने कहा कि खाद्य सुरक्षा भारत और अफ्रीका को जोड़ती है। भारत ने मानवीय सहायता के रूप में विभिन्न अफ्रीकी देशों को 1.58 करोड़ डॉलर की खाद्य सहायता उपलब्ध कराई है। मुरलीधरन ने कहा, ''भारत ने घरेलू मांग को पूरा करने के लिये दाल आयात को लेकर मलावी और मोजाम्बिक के साथ समझौते किये हैं। फिलहाल हम दाल के आयात को लेकर कुछ और अफ्रीकी देशों के साथ समझौता ज्ञापन पर बातचीत कर रहे हैं।'' भारत दाल का सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता देश है। उन्होंने कहा कि अफ्रीका के पास काफी भूमि है जिसे वह विभिन्न उत्पादों के उत्पादन के लिये उपलब्ध करा सकता है। मंत्री ने कहा, ''भारत बड़े पैमाने पर रोजगार और आय पैदा करने के साथ कृषि-प्रसंस्करण सुविधाओं के निर्माण के माध्यम से.... विदेशों में निवेश करने और फसलों का उत्पादन करने का अवसर तलाशना चाहता है।''

उन्होंने कहा कि निजी क्षेत्र की कंपनियां पहले ही कई अफ्रीकी देशों

चार माह के उच्चस्तर पर पहुंचा अगस्त में निर्यात, 45.76 प्रतिशत बढ़कर 33.28 अरब डॉलर हुआ

नई दिल्ली। आईपीटी नेटवर्क

देश का निर्यात पिछले महीने अगस्त में 45.76 प्रतिशत बढ़कर 33.28 अरब डॉलर पर पहुंच गया। हालांकि, इस दौरान व्यापार घाटा बढ़कर 13.81 अरब डॉलर के चार माह के उच्चस्तर पर पहुंच गया। वाणिज्य मंत्रालय के मंगलवार को जारी आंकड़ों में यह जानकारी दी गई है। मुख्य रूप से इंजीनियरिंग, पेट्रोलियम उत्पाद, रत्न एवं आभूषण तथा रसायन जैसे क्षेत्रों के बेहतर प्रदर्शन की वजह से निर्यात बढ़ा है। एक साल पहले अगस्त, 2020 में निर्यात 22.83 अरब डॉलर रहा था।

व्यापार घाटा बढ़कर 13.81 अरब डॉलर पर पहुंचा

आंकड़ों के अनुसार, अगस्त, 2021 में आयात 51.72 प्रतिशत बढ़कर 47.09 अरब डॉलर रहा। एक साल पहले इसी महीने में यह 31.03 अरब डॉलर रहा था। इस प्रकार अगस्त 2021 में व्यापार घाटा बढ़कर 13.81 अरब डॉलर पर पहुंच गया, जो पिछले साल इसी महीने में 8.2 अरब डॉलर रहा था। इससे पहले अप्रैल, 2021 में व्यापार घाटा 15.1 अरब डॉलर रहा था। चालू वित्त वर्ष के पहले पांच माह अप्रैल-अगस्त, 2021 में कुल निर्यात 67.33 प्रतिशत बढ़कर 164.10 अरब डॉलर पर पहुंच गया, जो इससे पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि में 98.06 अरब डॉलर रहा था। वहीं, अप्रैल-अगस्त, 2021 के दौरान आयात 219.63 अरब डॉलर पर पहुंच गया, जो इससे पिछले वित्त वर्ष के पहले पांच माह में 121.42 अरब डॉलर रहा था।

सोने का आयात 82.48 प्रतिशत के उछाल के साथ 6.75 अरब डॉलर पर

इस तरह वित्त वर्ष के पहले पांच माह में व्यापार घाटा 55.54 अरब डॉलर रहा है जो कि इससे पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि में 23.35 अरब डॉलर रहा था। अगस्त में देश का कच्चे तेल का आयात 80.64 प्रतिशत बढ़कर 11.65 अरब डॉलर पर पहुंच गया। वहीं इस दौरान सोने का आयात 82.48 प्रतिशत के उछाल के साथ 6.75 अरब डॉलर रहा। इंजीनियरिंग निर्यात माह के दौरान क्रमशः 59 प्रतिशत बढ़कर 9.64 अरब डॉलर रहा। वहीं पेट्रोलियम उत्पादों का निर्यात 144.6 प्रतिशत के उछाल से 4.65 अरब डॉलर पर पहुंच गया, जबकि रत्न एवं आभूषणों का निर्यात 88.3 प्रतिशत बढ़कर 3.43 अरब डॉलर पर पहुंच गया। इस दौरान रसायन निर्यात 36 प्रतिशत बढ़कर 2.23 अरब डॉलर रहा।

निर्यातकों के प्रमुख संगठन फियो के पूर्व अध्यक्ष एस के सराफ ने कहा कि निर्यात वृद्धि मजबूत है और भारत चालू वित्त वर्ष में 400 अरब डॉलर का निर्यात लक्ष्य हासिल करने की ओर अग्रसर है। फियो के अध्यक्ष ए शक्तिवेल ने कहा कि सरकार को कंटेनरों का प्रवाह बढ़ाने के लिए कदम उठाना चाहिए। इसके अलावा ढुलाई भाड़े में वृद्धि पर एक नियामकीय प्राधिकरण गठित करने और शिपिंग लाइंस द्वारा विभिन्न शुल्क लगाने के मामले में सरकार को तत्काल हस्तक्षेप करने की जरूरत है।

सितंबर में व्यापार घाटा कम होकर 10 अरब डॉलर पर आ सकता है

उन्होंने सरकार से 31 मार्च तक निर्यात के लिए ढुलाई समर्थन उपलब्ध कराने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि ढुलाई दरें इस समय आसमान पर हैं। इक्रा की मुख्य अर्थशास्त्री अदिति नायर ने कहा कि मुख्य रूप से सोने और कच्चे तेल के आयात की वजह से व्यापार घाटा बढ़ा है। नायर ने कहा कि आने वाले समय में सोने का आयात कम होने की संभावना है। ऐसे में सितंबर में व्यापार घाटा कम होकर 10 अरब डॉलर पर आ सकता है।

सतर्कता और दूरदर्शिता ही विद्युत सुरक्षा का आधार...

बिजली इंजीनियरों की तीन दिनी ट्रेनिंग के समापन पर बोले प्रबंध निदेशक

इंदौर। आईपीटी नेटवर्क

ट्रेनिंग कर्मचारियों, अधिकारियों की दक्षता बढ़ाने और नए तौर तरीकों से विभागीय कामकाज को आसान व सुरक्षित बनाती है। बिजली संबंधी सेवाओं में सतर्कता, सुरक्षा उपकरणों के उपयोग और दूरदर्शिता से ही बचाव होता है। सावधानी से दुर्घटना टाली जा सकती है। इंजीनियर ट्रेनिंग की बातों को दैनिक कार्य प्रणाली में शामिल करे और मैदानी वातावरण को सुरक्षित बनाए।

मध्यप्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के प्रबंध निदेशक श्री अमित तोमर ने उक्त प्रेरक उद्बोधन दिया। वे पोलोग्राउंड स्थित सभागार में ग्रामीण विद्युतीकरण निगम विद्युत प्रबंधन और प्रशिक्षण संस्थान हैदराबाद के तत्वावधान विद्युत सुरक्षा को लेकर तीन दिनी प्रशिक्षण का समापन सत्र को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि ट्रेनिंग का महत्व तभी रहेगा, जब इसकी बातों का असर मैदानी कार्यों में नजर आए। संयुक्त सचिव श्री तरूण उपाध्याय ने कहा कि कंपनी कार्मियों को नई तकनीक के साथ ही सुरक्षित वातावरण में सावधानी, सजगता के साथ विद्युत संबंधी कार्य करने की सतत कोशिश कर रही है। इस मामले में मैदानी अमले से हर बातों व तथ्यों पर अक्षरशः अमल करने का आह्वान करता हूं। इस दौरान अर्थिंग के महत्व, ग्रिड के कार्यों में सगजता एवं सावधानी, आग लगने पर बचाव व सावधानी के कार्य आदि की विशेष जानकारी भी दी गई। मप्र पुलिस के फायर फायटर कर्मचारियों ने अधिकारी श्री बीएस हुड्डा के नेतृत्व में आग बुझाने का सजीव प्रदर्शन किया। समापन मौके पर प्रशिक्षण में शामिल इंजीनियरों को प्रमाण पत्र भी वितरित किए गए। इस अवसर पर कार्यपालक निदेशक श्री संजय मोहासे, मुख्य अभियंता श्री एसएल करवाड़िया, अतिरक्त मुख्य अभियंता श्री आरके नेगी के साथ ही हैदराबाद के प्रशिक्षक श्री बी. मुरलीधर राव, श्री एसएच वाईकर आदि विशेष रूप से मौजूद थे। संचालन श्रीमती रूपाली गोखले ने किया। आभार माना उप महाप्रबंधक मानव संसाधन श्रीमती सपना दामेशा ने।

आवाज के जरिये जल्द कर पाएंगे लेनदेन

60 करोड़ से अधिक फीचर फोन उपयोगकर्ताओं को मिलेगा लाभ

नई दिल्ली। आईपीटी नेटवर्क

आवाज के जरिये वित्तीय लेनदेन जल्द ही एक वास्तविकता बनने जा रहा है। रिजर्व बैंक ने इस तरह के भुगतान के लिए हार्डवेयर-एग्नॉस्टिक ध्वनि तरंग आधारित तकनीकी समाधान प्रदाता टोनटैग को मंजूरी दे दी है। कंपनी ने मंगलवार को कहा कि टोनटैग ने खुदरा भुगतान के लिए भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के सैंडबॉक्स के तहत पहले दस्ते का परीक्षण चरण पूरा कर लिया है। कंपनी ने कर्नाटक और बिहार के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में परीक्षण किया जिसमें 1,000 रुपये तक के लेनदेन शामिल थे। टोनटैग 600 मिलियन (60 करोड़) से अधिक फीचर फोन उपयोगकर्ताओं के लिए डिजिटल भुगतान को सक्षम बनाने की तैयारी में है।

रिजर्व बैंक से मंजूरी मिली

टोनटैग ने कहा कि उसने अस्थिर इंटरनेट कनेक्टिविटी वाले क्षेत्रों में फीचर फोन और स्मार्ट फोन के माध्यम से ऑफलाइन आवाज-आधारित भुगतानों को सफलतापूर्वक पूरा किया है। बेंगलुरु की कंपनी ने कहा, प्रौद्योगिकी पहले से ही मौजूद है, हमें रिजर्व बैंक से मंजूरी मिल गई है, अब विनियमित इकाइयां इस तकनीक को आसानी से अपना सकती हैं।

हर कोई आसानी से कर पाएगा इस्तेमाल

उसने कहा कि इससे उन लोगों को लाभ होगा जो डिजिटल मंचों का इस्तेमाल करने के आदि नहीं हैं या जिन्हें बैंकिंग या भुगतान के लिए ऐप का इस्तेमाल करना मुश्किल लगता है। कंपनी ने कहा कि इस तरह यह नई सुविधा डिजिटल भुगतान को सभी के लिए एक वास्तविकता बना देगी और यह तकनीक अब सेवा प्रदाताओं द्वारा अपनाए जाने के लिए तैयार है।

भारत, आसियान के बीच हवाई संपर्क पर और ध्यान देने की जरूरतः सोनोवाल

नयी दिल्ली। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने मंगलवार को कहा कि भारत और आसियान (दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के संगठन) के बीच क्षेत्र के अनछुए इलाकों में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हवाई संपर्क पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। बंदरगाह, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री ने द्विपक्षीय व्यापार बढ़ाने के लिये आसियान देशों के साथ क्षेत्रीय संपर्क परियोजना में तेजी लाने की जरूरत बतायी।

उन्होंने कहा, ''हमें भारत और आसियान के बीच क्षेत्र के अनछुए इलाकों में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हवाई संपर्क पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है।'' मंत्री ने भविष्य की भारत-आसियान संपर्क भागीदारी विषय पर उद्योग मंडल फिक्की के सम्मेलन को संबोधित करते हुए यह बात कही। सोनोवाल ने कहा, ''इसके अलावा हम समझौते की जल्द समीक्षा करने पर भी विचार कर रहे हैं जिससे दोनों पक्षों के बीच वास्तविक व्यापार क्षमता हासिल करने में मदद मिलेगी।'' समीक्षा में सीमा शुल्क प्रक्रिया तथा व्यापार को और उदार बनाने जैसे मुद्दों को शामिल किये जाने की उम्मीद है। मंत्री ने कहा कि 10 आसियान देशों में से केवल पांच देशों - मलेशिया, म्यांमा, सिंगापुर, वियतनाम और थाईलैंड - के साथ भारत की सीधी उड़ान सेवाएं है। जबकि कंबोडिया, इंडोनेशिया और फिलीपीन सहित अन्य पांच देशों के साथ कोई सीधी उड़ान नहीं है। उन्होंने कहा कि इंडोनेशिया और फिलीपीन दो प्रमुख देश हैं जिनके साथ भारत का पर्याप्त व्यापार और पर्यटन हित है। सोनोवाल ने कहा, ''हमारा मानना है कि स्थिति में रूपांतरण केवल चीजों में बदलाव के माध्यम से संभव है और अगर इसे हासिल करना है तो संपर्क और संचार जरूरी है।''

स्वामी/मुद्रक/प्रकाशक सचिन बंसल द्वारा अपनी दुनिया प्रिंटर्स, 13, प्रेस काम्पलेक्स, ए.बी. रोड, इंदौर से मुद्रित एवं 18, सेक्टर-डी-2, सांवेर रोड, इंडस्ट्रीयल एरिया, जिला इंदौर (म.प्र.) से प्रकाशित। संपादक- सचिन बंसल

सूचना/चेतावनी- इंडियन प्लास्ट टाइम्स अखबार के पूरे या किसी भी भाग का उपयोग, पुनः प्रकाशन, या व्यावसायिक उपयोग बिना संपादक की अनुमति के करना वर्जित है। अखबार में छपे लेख या विज्ञापन का उद्देश्य सूचना और प्रस्तुतिकरण मात्र है। अखबार किसी भी प्रकार के लेख या विज्ञापन से किसी भी संस्थान की सिफारिश या समर्थन नहीं करता है। पाठक किसी भी व्यावसायिक गतिविधि के लिए स्वविवेक से निर्णय करें। किसी भी विवाद की स्थिति में न्याय क्षेत्र इंदौर, मप्र रहेगा।